https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

प्रधानमंत्री ने किया क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' का शुभारंभ

वर्ष-12, अंक-10, 16-31 मई, 2017 (पाक्षिक) ₹20

'एबार बांग्ला'

दिल्ली नगर निगम चुनाव: भाजपा ने लगाई जीत की हैट्रिक

उज्ज्वला से उजाला

भारतीय संदर्भ में विकास की संकल्पना

पश्चिम बंगाल एवं जम्मू–कश्मीर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के प्रवास की तस्वीरें

भवानीपुर स्थित बूथ न. 269 पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

पश्चिम बंगाल में पं. दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना का शुभारंभ करते श्री अमित शाह

कोलकाता में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के पैतृक निवास का दौरा करते श्री अमित शाह

जम्मू स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष एवं कार्य विस्तार योजना के निमित्त आयोजित बैठक को संबोधित करते श्री अमित शाह

जम्मू एयरपोर्ट पर श्री अमित शाह के आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत

प्रदेश भाजपा कार्यालय, जम्मू में नानाजी देशमुख पुस्तकालय एवं ई–लाइब्रेरी का उद्घाटन करते श्री अमित शाह

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइटः www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 ## 'तृणमूल नेता जितना हिंसा का कीचड़ फैलाएंगे, कमल उतना ही अधिक खिलकर निकलेगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 25 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से पंडित दीनदयाल कार्य विस्तारक योजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस योजना के अंतर्गत 15 दिनों...

वैचारिकी

कांग्रेस बनाम जनसंघ 16

श्रद्धांजलि

नहीं रहे विनोद खन्ना 17

लेख

उज्ज्वला से उजाला 18

भारतीय संदर्भ में विकास की संकल्पना 20

अन्य

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का 95 दिनों का प्रवास तय 12

कांग्रेस सरकार प्रदेश का विकास नहीं कर सकती 22

'माणिक सरकार ने दस हजार शिक्षकों को बेरोजगार करने... 24

'भाजपा सरकार ने रिफॉर्म्स के बदले ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी... 25

'हमारे कार्यों से दिल्ली के गरीब लोगों के जीवन में सकारात्मक... 27

जीएसएलवी ने दक्षिणी एशियाई उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया 29

पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (दिल्ली) का लगभग 60 फीसदी... 30

भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर 31

'बुराइयों के खिलाफ लड़ने का माद्दा हमारे भीतर ही पैदा हुआ' 32

हर व्यक्ति का महात्म्य हैः नरेंद्र मोदी 33

संगठनात्मक गतिविधियां

10 **दिल्ली नगर निगम चुनावः भाजपा ने लगाई जीत की हैट्रिक**

चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भाजपा ने अपना वोट शेयर लगभग 5...

11 **लोगों ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया : अमित शाह**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा की दिल्ली नगर...

सरकार की उपलब्धियां

13 **भू सम्पदा अधिनियम एक मई से प्रभावी**

नौ वर्ष से लम्बित भू सम्पदा क्षेत्र का नियमन एक मई 2017 से भू सम्पदा (विनियमन...

14 **माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज फेसिलीटेशन काउंसिल पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ**

केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

हमारी संस्कृति को दबाने का जो काम गैरों ने किया, उससे तो हम लड़ पाए, लेकिन इसे भुलाने का जो काम अपनों ने किया, उसने बहुत क्षति पहुंचायी।

@rajnathsingh

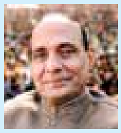

मेरा यह विश्वास है कि बन्दूक के बल पर विकास और लोकतंत्र को झुकाने और दबाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी।

@arunjaitley

हमारे दो सैनिकों की मृत्यु और विकृत करने का कार्य अत्यंत निन्दनीय एवं बर्बरतापूर्ण कार्य है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।

facebook

त्रिपुरा में गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों के नाम पर जो कम्युनिस्ट सरकार शासन कर रही है, उसने भ्रष्टाचार और दमन के अलावे कुछ भी नहीं किया है। जब तक त्रिपुरा में माकपा की सरकार है, तब तक यहां विकास संभव नहीं है। त्रिपुरा की जनता विकास चाहती है जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है।

— अमित शाह

विदिशा स्थित फार्म का अवलोकन कर आनंदित हूं। अपनी उद्यानिकी फसलों को बढ़ते देखकर खुशी होती है। फसलों का बड़ा होना हर किसान के लिए बड़ी खुशी लेकर आता है। उद्यानिकी फसलें सदैव लाभकारी होती हैं, क्योंकि इन पर मौसम की मार का अधिक असर नहीं होता है और बाज़ार में कीमत भी अच्छी मिल जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे किसान भाई भी उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में रुचि लें।

— शिवराज सिंह चौहान

व्यंग्य चित्र

साभार: जनसत्ता

'कमल संदेश' की ओर से सुधी पाठकों को

शनि जयंती

की हार्दिक शुभकामनाएं!

पाथेय

भारत की समस्याएं केवल तभी हल की जा सकती हैं, जब हम भारत को समझे। यदि हम बाहर गांव में मलिन बस्तियों में वनवासी क्षेत्रों में और ऐसे स्थानों में जहां अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, न जाये तो हम भारत को कैसे समझ सकते हैं? यदि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सभी प्रदेशों और समाज के सभी वर्गों में फैल नहीं जाते हैं, यदि हम उनके विशिष्ट इतिहास तथा रीति–रिवाजों और समस्याओं और शक्तियों की ठोस जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, तो हम उन्हें अपनी पार्टी के अधिक निकट कैसे ला सकते हैं?

-कुशाभाऊ ठाकरे

आप ही बेनकाब हो गई 'आप'

अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। अपने ही मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा दो करोड़ के रिश्वत का अपने एक अन्य मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा आरोप का उत्तर उन्होंने कपिल मिश्रा के निलंबन के द्वारा दिया। एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई, जबकि एक मुख्यमंत्री अपने ही एक मंत्री से एक दूसरे मंत्री की उपस्थिति में रिश्वत लेता है। जनता के लिए यह विश्वासघात से कम नहीं जब अरविंद केजरीवाल इस आरोप पर अपना स्पष्टीकरण तक देने से इंकार कर देते हैं। एक ओर जब केजरीवाल अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं, वहीं दूसरी ओर अपनी जवाबदेही से भागने के कारण उन पर अनेक प्रश्न खड़े हो गये हैं। यह विचित्र विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने शुचिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मुद्दे पर सत्ता प्राप्त की, आज उसमें इतना भी नैतिक बल नहीं बचा कि जनता से आंखें मिलाकर बात कर सके। अपने राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों पर आधारहीन आरोपों की झड़ी लगाकर इस्तीफे की मांग करने वाला व्यक्ति आज जनता से मुंह चुराता फिर रहा है।

अपने जन्म से ही आम आदमी पार्टी (आप) अनगिनत विरोधाभासों से भरी रही है। कथनी और करनी में दिनों-दिन गहराती खाई शुरू से दिखने लगी थी। दिल्ली में स्वयं को प्रमाणित कर जनता का दिल जीतने की जगह यह पूरे देश में अपनी महत्वाकांक्षाओं के सपने देखने लगी। जैसे ही केजरीवाल के महत्वाकांक्षा पर गोवा और पंजाब की जनता ने पानी फेर दिया, दिल्ली की राजौरी गार्डेन सीट पर हुए उपचुनाव में इनकी जमानत तक जब्त हो गई। लगता है इतना ही काफी नहीं था, दिल्ली में हुए नगर निकाय चुनावों ने आप को बुरी तरह से धूल चटाकर जनता ने पूरी कसर निकाल ली। जहां भाजपा को भारी विजय प्राप्त हुई आप को कुछ ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने की जगह केजरीवाल ने अपनी इस अपमानजनक हार का ठीकरा ईवीएम मशीनों पर फोड़ना चाहा, पर उनके ही दल के कुछ नेताओं ने इस पर भी उन्हें भरपूर आइना दिखाया। आत्ममंथन की जगह दुर्भावनापूर्ण प्रश्न खड़े कर केजरीवाल ने अब जनता को अपने से बहुत दूर कर लिया है। अब वे एक सत्ता के लिए भूखे नेता की तरह दिखाई दे रहे हैं जो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। आखिर जनता ने केवल दो वर्षों में आप को कठोर दण्ड दे ही दिया। सच तो यह है कि भ्रष्टाचार एवं रिश्वत के आरोपों ने आप के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। पार्टी भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और अनैतिकता के दल-दल में इतनी धंस चुकी है जिसका अंदाजा तक लगाना अब जनता के लिए कठिन जान पड़ता है। केवल दो वर्षों में इसके सात में से छह मंत्रियों को गंभीर आरोपों के कारण त्यागपत्र देना पड़ा और अब स्वयं मुख्यमंत्री कठघरे में खड़े हैं।

क्या कारण है कि जो पार्टी देश में राजनीति की गंदगी साफ करने का और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज होने का दावा करती थी वह स्वयं इतने कम समय में हर प्रकार की राजनैतिक गंदगी की शिकार हो गई ? इसका भी उत्तर बहुत कठिन नहीं है-इसने दिन-रात अपने ही एजेण्डे के विपरीत काम किया और बड़ी तेजी से देश में राजनैतिक बेईमानी और धोखाधड़ी का सबसे बड़ा रिकार्ड बना दिया। आरंभ से ही पार्टी ने एक व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था को आगे बढ़ाया जिससे पार्टी में एक व्यक्ति अधिनायकवाद स्थापित हुआ है। अपना कद सबसे ऊंचा करने के लिए एक ओर केजरीवाल ने जहां जनता के धन का खुलेआम दुरूपयोग किया, वहीं दूसरी ओर किसी भी संभावित चुनौती को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाने में देरी नहीं की। इस तरह के स्वकेंद्रित एवं स्वार्थी राजनीति के कारण आप में कभी आंतरिक लोकतंत्र ठीक से पनप नहीं पाया। इसलिए अब जब केजरीवाल कठघरे में है, आप के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। राजनीति में तुरंत सफलता आप के नेताओं के सिर पर चढ़कर बोलने लगी, जिससे वे जनभावनाओं को हल्के में लेने लगे तथा शुचिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही उनके लिए मात्र एक जुमला बनकर रह गया। अपने कुशासन एवं अकर्मण्यता को छुपाने के लिए बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनर्गल आरोप लगाने से जनता के बीच इनकी बची-खुची साख भी खत्म हो चुकी है। साथ ही जिस प्रकार से हर हार पर आप के नेता जनता को जवाब दे रहे हैं, उससे उनके लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता पर भी प्रश्न चिह्न खड़ा हो चुका है। इससे यही लगता है कि आप नेताओं को गुमान है कि वे जनता को जब चाहे तब मूर्ख बना सकते हैं और जनता का ध्यान अपने कुशासन से भटका सकते हैं। केजरीवाल शायद यह भूल गये हैं कि जनता बार-बार उन्हें माफ नहीं करेगी और इस बार तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा ही पार कर दी है। अब इतना ही कहा जा सकता है कि आप अब खुद ही अपने को बेनकाब करने में उलझी हुई है। ■

अब जब केजरीवाल कठघरे में है, आप के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। राजनीति में तुरंत सफलता आप के नेताओं के सिर पर चढ़कर बोलने लगी, जिससे वे जनभावनाओं को हल्के में लेने लगे तथा शुचिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही उनके लिए मात्र एक जुमला बनकर रह गया। अपने कुशासन एवं अकर्मण्यता को छुपाने के लिए बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनर्गल आरोप लगाने से जनता के बीच इनकी बची-खुची साख भी खत्म हो चुकी है।

shivshakti@kamalsandesh.org

'तृणमूल नेता जितना हिंसा का कीचड़ फैलाएंगे, कमल उतना ही अधिक खिलकर निकलेगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 25 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से पंडित दीनदयाल कार्य विस्तारक योजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस योजना के अंतर्गत 15 दिनों तक पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, गुजरात एवं उड़ीसा में तीन-तीन दिन तक बूथ में प्रवास कर पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे और इस अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। नक्सलबाड़ी के बूथ संख्या 93 में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने से पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक गरीब परिवार में भोजन किया, इसके बाद उन्होंने 60 बूथ कार्यकर्ताओं के साथ लगभग सवा घंटे तक बातचीत की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

भाजपा अध्यक्ष ने देश के पूर्वी भाग के अंतिम गांवों में से एक गांव कठाईगाई में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां बूथ से लेकर देश के अध्यक्ष नक्सलबाड़ी के इस गांव में आये हुए हैं, यह गांव भूटान, नेपाल और बंगलादेश के बॉर्डर पर स्थित है। उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता कि भारतीय सीमा पर बसे अंतिम गांवों में से एक इस गांव में आकर मुझे कितना हार्दिक आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब नक्सलबाड़ी के गांव में कमल खिला हुआ देखते हैं तो ह्रदय आनंद से गद्‌गद्‌ हो उठता है। उन्होंने कहा कि यह वही नक्सलबाड़ी है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, आज भी उस हिंसा में पूरा देश झुलस रहा है, आज उसी नक्सलबाड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हिंसा पर विकास की विजय निश्चित रूप से होगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पहले कम्युनिस्टों और फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार चली है, उससे यह

प्रदेश गरीब से गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला कहलाने वाला यह प्रदेश कभी देश के समृद्ध प्रदेशों में से एक था, आज यह बेरोजगारी, हिंसा और तुष्टीकरण का केंद्र बन गया है, आज यहां हर जगह अराजकता का माहौल दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज यहां के लोगों का जो उत्साह मैंने यहां देखा है, उससे मुझे निश्चित भरोसा है कि पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं यहां के सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि इतनी हिंसा के बावजूद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम करना और उसे आगे बढ़ाने जारी रखा है।

श्री शाह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तारक योजना को लेकर 15 दिन, 6 महीना और साल भर पार्टी के विस्तार के लिए गांव-गांव, घर-घर जाने वाले हैं और देश भर के कई गांवों में पूरा-पूरा दिन बिताने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती कार्य विस्तारक योजना के अंतर्गत 3 लाख 68 हजार कार्यकर्ताओं ने अपना 15 दिन का पूरा समय पार्टी की योजना के अनुरूप घर से बाहर जाकर विस्तारक के रूप में देने और कार्य करने का तय किया है। इसके अतिरिक्त 4 हजार कार्यकर्ताओं ने 6 माह तथा 1 वर्ष के लिए पूरा समय पार्टी के काम को आगे बढ़ाने और विस्तार देने के लिए तय किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंसा का दौर चाहे जितना भी लंबा हो, हमेशा नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में उद्भव, विस्तार और अंत में विजय सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसका परिचय आने वाले 2019 के चुनाव में देश की जनता देने वाली है। पश्चिम बंगाल की जनता भी इसका परिचय कराने वाली है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तो ठीक से चल रही है लेकिन पश्चिम बंगाल में गांव के गरीब बहनों के घर में गैस पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को यदि लगता है कि विकास कार्यों में बाधा डाल कर वे मोदी जी के रथ को रोक पायेंगे तो यह उनकी भूल है। उन्होंने कहा कि मैं तृणमूल

के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप जितना दमन करेंगे, आप जितना अत्याचार करेंगे, जितना हिंसा का कीचड़ फैलायेंगे, कीचड़ में से कमल उतना ही अधिक खिलकर बाहर निकलेगा।

श्री शाह ने कहा कि मैंने कई सभाओं को संबोधित किया है, हजारों-लाखों की भीड़ को संबोधित किया है, लेकिन गांव के नुक्कड़ पर यह छोटी सी सभा मेरे मन को असीम संतोष और आनंद देने वाली है। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान की सरहद पर ये गांव जो तीन देशों की सीमाओं से जुड़ता है और जहां से नक्सलवाद का विचार पनपा, आगे बढ़ा और अब अंत की ओर जा रहा है, तब आज यहां भी कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह देश के करोड़ों लोगों के लिए और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण दिन है। ■

'सोनार बांग्ला के नवनिर्माण में भाजपा के साथ आएं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने 15 दिवसीय पंडित दीनदयाल कार्य विस्तारक योजना के तीन दिन के पश्चिम बंगाल में बूथ प्रवास के दूसरे दिन प्रेस क्लब, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में 26 अप्रैल को आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस संबोधित किया और पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी, हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जम कर प्रहार किया। उन्होंने दिल्ली नगर निगम के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत के लिए दिल्ली की जनता के प्रति अपना हार्दिक आभार भी व्यक्त किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल जन्मशताब्दी कार्य विस्तारक योजना के अंतर्गत साढ़े तीन लाख से अधिक कार्यकर्ताओं 15 दिन, 6 महीना और साल भर के लिए अपना पूरा समय बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्य व विचारधारा के विस्तार के लिए देना तय किया है। इसके तहत मैं भी पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, लक्षद्वीप व गुजरात में तीन-तीन दिन का प्रवास कर बूथ स्तर पर पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा जैसे राज्यों में पार्टी के कामकाज व विचारधारा के विस्तार और बूथ-स्तर पर पार्टी की मज़बूती के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि अपने 15 दिवसीय पंडित दीनदयाल जन्मशताब्दी कार्य विस्तारक योजना के पहले दिन उत्तर बंगाल के नक्सलबाड़ी में बूथ नंबर 93 पर मेरा प्रवास था, उत्तर बंगाल में आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जनसमर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।

श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि राज्य में जब वामपंथी शासन का अंत हुआ तो लोगों को प्रदेश के विकास को लेकर एक नई आशा की किरण

दिखाई दी, लेकिन तृणमूल सरकार के 6-7 वर्षों के शासनकाल से उन्हें केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बात देश के विकास में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 25% थी जबकि आज यह घट कर 4% के आस-पास आ गई है, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि पहले कम्युनिस्टों और अब तृणमूल के शासन में पश्चिम बंगाल विकास में अपनी हिस्सेदारी तेजी से गंवा रहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जब वामपंथी शासन का अंत हुआ तब राज्य की जनता पर 1 लाख 92 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जबकि अभी तृणमूल सरकार के वक्त राज्य की जनता पर 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का ऋण है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार बंद होने का नाम नहीं ले रही है, राज्य में आज हर तरफ सादगी के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे शारदा हो या नारदा, नैतिकता के आधार पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार किसी भी सवाल पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है, राज्य की जनता उनसे हिसाब मांग रही है।

श्री शाह ने कहा कि देश की आज़ादी के समय बैंक डिपोजिट के रूप में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 18% थी, कम्युनिस्ट पार्टियों के शासन के अंत में यह हिस्सेदारी घट कर 12.8% रह गई, जबकि वर्तमान में ममता दीदी की सरकार में यह अपने निम्नतम स्तर 6.3% पर आ गई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह बैंक क्रेडिट के मामले में भी पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी वर्तमान में 9.8% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में मात्र 5% है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एफडीआई के अंतर्गत 2% से भी कम निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि विद्युत खपत के मामले में भी राज्य के प्रति व्यक्ति विद्युत की कुल खपत राष्ट्रीय औसत के मुकाबले लगभग 30% कम है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में उत्पादन के क्षेत्र में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, राज्य का हर पांचवां व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीने को विवश है, कृषि विकास दर भी काफी कम है और मज़दूरों की स्थिति भी काफी दयनीय है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको लेकर राज्य की जनता में काफी गुस्सा और आक्रोश है। उन्होंने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के लिए भी क्या हमें हाईकोर्ट से निर्देश लेने पड़ेंगे। क्या सरस्वती पूजा को भी राज्य की तृणमूल सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती-इससे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार जनता से भेदभाव कर रही है। नोटबंदी का विरोध कर के तृणमूल ने पूरे देश में अपनी जगहंसाई करवाई है। जाली नोटों पर अंकुश लगाने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने में भी राज्य की तृणमूल सरकार पूर्णतया विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि एक समय था, जब पश्चिम बंगाल उद्योग-कारखानों का केंद्र था, आज पश्चिम बंगाल में सारे उद्योग-धंधे ठप्प पड़ गए हैं, केवल बम बनाने के कारखाने चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रवींद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मई में जुरांवपुरा में हत्याकांड की घटना हो, जनवरी 2016 को राज्य में हुआ जनसंहार हो या फिर अक्टूबर 2016 में मेदनीपुर में हुई

हिंसा की घटना हो, राज्य की जनता इससे व्यथित भी है और आक्रोशित भी।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल को जहां 13539 करोड़ रुपये की राशि मिलती थी, वहीं 14वें वित्त आयोग में भाजपा-नीत एनडीए सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल को यूपीए सरकार की तुलना में लगभग तीन गुना 289942 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रान्टिंग एड में भी पश्चिम बंगाल को

यूपीए सरकार के 9520 करोड़ रुपये के सापेक्ष मोदी सरकार द्वारा 34732 करोड़ रुपये देने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल को 11760 करोड़ रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी मिला है, जबकि कांग्रेस के समय पश्चिम बंगाल को इस तरह का कोई ग्रांट ही नहीं मिलता था। स्टेट डिजास्टर ग्रांट में भी यूपीए सरकार के 1263 करोड़ रुपये की तुलना में प्रदेश को इस बार मोदी सरकार में 2140 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और लोकल बॉडीज ग्रांट में भी पश्चिम बंगाल को इस बार यूपीए सरकार के 1944 करोड़ रुपये की तुलना में 20832 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने केवल मनरेगा के जरिये पश्चिम बंगाल के 51 लाख घरों में रोज़गार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य में ग्रामीण सड़कों व गरीबों के घर के निर्माण के लिए भी करोड़ों रुपये की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा समझौता कर के पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पर भी अंकुश लगाने के लिए काफी ठोस कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार ने काफी प्रयास किये हैं, स्वामी विवेकानंद ट्रेन की शुरुआत की गई है, एक वर्ष में 80 से ज्यादा सबवे का निर्माण हुआ है, 123 रेलवे क्रॉसिंग को मानव-रहित बना दिया गया है, स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, कई रेलवे ओवरब्रिज व अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है, 21 नए एसी रिटायरिंग रूम बनाए गए हैं और रेलवे के विकास के लिए अन्य कार्यों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 24 घंटे बिजली

पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको लेकर राज्य की जनता में काफी गुस्सा और आक्रोश है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के लिए भी क्या हमें हाईकोर्ट से निर्देश लेने पड़ेंगे। क्या सरस्वती पूजा को भी राज्य की तृणमूल सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती?

आपूर्ति के लिए विशेष योजनायें तैयार की गई हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत राज्य के 29 जिलों के लिए लगभग 4262 करोड़ रुपये आवंटित की गई है, एकीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए अलग से 1075 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और साथ ही 131 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का काम भी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी

पश्चिम बंगाल में संगठन विस्तार कर रही है और अभी हाल ही में राज्य में हुए दो उप-चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रह कर प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में आई है, उस आधार मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राज्य की जनता का भरोसा इसी गति से भाजपा में बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम 2019 में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लोक सभा सीटें जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होने के लक्ष्य को सामने रख कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती कार्य विस्तारक योजना के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता 15 दिन, 6 महीने और एक साल के लिए राज्य के घर-घर जाकर दीनदयाल जी के व्यक्तित्व, पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं से जनता को रू-ब-रू करायेंगे।

श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हिंसक हमले किये जा रहे हैं। वीभत्स अत्याचार किये जा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, यदि तृणमूल कांग्रेस यह समझती है कि हिंसा के जरिये, दबाव बनाकर वे भारतीय जनता पार्टी को रोक पायेंगे तो मैं ममता दीदी को कहना चाहता हूं कि ऐसा करने से प्रदेश में कमल मुरझायेगा नहीं, बल्कि और अच्छे तरीके से खिलकर राज्य की जनता के सामने स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मैं मानता हूं कि यह पश्चिम बंगाल की संस्कृति और संस्कार पर कुठाराघात है और इसके विरोध में राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय के बाद पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 'एबार बांग्ला' अर्थात् अबकी बार पश्चिम बंगाल का सूत्र लेकर राज्य के मतदाताओं के घर-घर तक जायेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजय रथ को और भी दिग्विजयी बनाने का काम करेंगे और साथ ही मोदी जी के विकास कार्यों और गरीब-कल्याण नीतियों का प्रचार-प्रसार करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की जनता से करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि सोनार बांग्ला के नवनिर्माण में वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आयें और इस विकास-यात्रा में भागीदार बनें। ■

भाजपा ने लगाई जीत की हैट्रिक
दिल्ली की तीनों निगमों में भारी बहुमत

चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भाजपा ने अपना वोट शेयर लगभग 5 प्रतिशत बढ़ाया, जबकि 'आप' को मिले वोट उसके पिछले आंकड़ों के अनुसार घट कर आधे रह गए। दिल्ली नगर निगम चुनावों में 2516 प्रत्याशियों में से, जिनमें आप के 40 और कांग्रेस के 92 प्रत्याशियों ने अपनी जमानत जमा गंवा दी।

26 अप्रैल 2017 को दिल्ली नगर निगम चुनावों में भाजपा ने 181 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। इस चुनाव में 'आप' और कांग्रेस की हालत पस्त हो गई। आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली विधानसभा में सत्ता में है, वह 48 सीट लेकर दूसरे नम्बर पर रही जबकि कांग्रेस केवल 30 सीटें और अन्य दल 10 सीटों पर किसी तरह जीत प्राप्त कर सके। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार, भाजपा ने लगभग 5 प्रतिशत का वोट शेयर बढ़ाया, जबकि आप पिछले आंकड़ों की तुलना में आधी सीटों पर रह गई। दिल्ली नगर निगम चुनावों में, 2516 उम्मीदवारों में से आप की 40 और कांग्रेस की 92 सीटों पर जमानत जब्त हो गई।

भाजपा ने सभी उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगमों में जीत हासिल की। भाजपा की विशेष रूप से पूर्वी नगर निगम में विजय उल्लेखनीय है, क्योंकि इस क्षेत्र में 2015 के विधानसभा चुनावों में

@AmitShah

दिल्ली नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की भव्य विजय पर प्रदेश अध्यक्ष श्री @ManojTiwariMP एवं सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई।

भारतीय जनता पार्टी को यह विशाल जन समर्थन देने के लिए दिल्ली प्रदेश की जनता का हृदय से अभिनंदन।

यह विजय देश की जनता में प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब-कल्याण योजनाओं एवं सबका साथ-सबका विकास की नीतियों में दिख रहे निरंतर विश्वास की जीत है।

दिल्ली की जनता ने बहानों एवं आरोपों की राजनीति को नकार कर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली विकासशील राजनीति में विश्वास व्यक्त किया है।

मुझे विश्वास है कि यह नवनिर्वाचित सदस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनकल्याणकारी नीतियों के अनुरूप दिल्ली का विकास करेंगे।

एमसीडी चुनाव 2017– सीटें और वोट प्रतिशत		
पार्टी	**सीट**	**वोट प्रतिशत**
भारतीय जनता पार्टी	181	36.08
आम आदमी पार्टी	48	26.23
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	30	21.09
निर्दलीय	6	8.44
बहुजन समाज पार्टी	3	4.44
इण्डियन नेशनल लोकदल	1	0.64
समाजवादी पार्टी	1	0.39
कुल	**270**	

आम आदमी पार्टी की स्थिति में गिरावट दर्ज हुई। इस बार, भाजपा प्रत्याशी ने 'आप' के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के वार्डों में जीत प्राप्त की।

दक्षिणी नगर निगम चुनावों में भाजपा ने 2012 में 44 सीटें प्राप्त की थी। इस बार पार्टी ने 60 वार्डों में से भी अधिक जीतीं हैं। 2015 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने दक्षिणी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इसलिए पार्टी के लिए एमसीडी का चुनाव बहुत बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के लोगों का आभार प्रगट किया कि उन्होंने भाजपा में अपनी आस्था जताई और एमसीडी में जोरदार जीत प्राप्त करने में मदद की।

उन्होंने ट्विटर पर संदेश देते हुए कहा कि मैं भाजपा में अपनी आस्था रखने के लिए आभार प्रगट करता हूं जिससे एमसीडी चुनावों में भारी विजय हासिल हुई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा कि सुकमा में नक्सलियों द्वारा 25 सीआरपीएफ की मृत्यु पर लोगों का दिल हार्दिक संवेदना से भर गया है और पार्टी इस अवसर पर विजय का उत्सव नहीं मनाएगी। हम इस विजय को सुकमा शहादत के चरणों में रखना चाहेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने आप पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो पार्टी 67 विधानसभा सीटों पर जीती, अब वह 67 वार्डों में भी प्रबंध करने में असफल रही। श्री मनोज तिवारी ने श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को इसका श्रेय दिया और श्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। ■

लोगों ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा की दिल्ली नगर निगम चुनावों में भारी जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एमसीडी चुनावों में भाजपा ने विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की विजय के परिणाम उसे और भी अग्रणीय बना देते हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और 'आप' सरकार पर भी चुटकी ली। श्री शाह ने कहा कि इन परिणामों से पता चलता है कि नकारात्मकता की राजनीति समाप्त हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की 'सबका साथ' की कल्याणकारी राजनीति ने 'ब्लेम गेम' और बहानों की राजनीति को समाप्त कर दिया है।

श्री शाह ने दिल्ली के लोगों को भाजपा में आस्था रखने पर धन्यवाद दिया और कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के किए गए तीन सालों तक के कार्य पर अपनी मोहर लगा दी है। श्री शाह ने श्री मनोज तिवारी और दिल्ली के अन्य कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' कार्यक्रम पर अपनी मोहर लगा दी है। भाजपा के लिए यह विजय बेमिसाल है। मैं दिल्ली के लोगों के प्रति अनुग्रहित हूं। यह विजय मोदी जी के नेतृत्व की जय-जय है। लागों ने नकारात्मक राजनीति और बहानों की राजनीति को नकार दिया है और मोदी जी के 'विजय रथ' को आगे बढ़ाया है।

इसने मोदी जी के नेतृत्व को मान्यता प्रदान की है।''

श्री शाह ने कहा कि 'हमारे विपक्षियों ने उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीत दिल्ली में रुक जाएगी, परन्तु पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से हमने जीत हासिल की। इस विजय ने भाजपा के लिए दिल्ली में सरकार बनाने की नींव रख दी है। दिल्ली के लोगों का आभार प्रगट करते हुए उन्होंने कहा कि एमसीडी के तीनों निकायों में लोगों ने हमें अप्रत्याशित बहुमत प्रदान किया है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का 95 दिनों का प्रवास तय

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का सभी राज्यों में कुल 95 दिनों के प्रवास का कार्यक्रम बना है जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती कार्य विस्तारक योजना के तहत पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप और गुजरात में 15 दिनों के बूथ-स्तर पर पार्टी के विस्तार का कार्यक्रम भी शामिल है। हाल ही में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में संपन्न भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद इसका एलान किया था कि वे इस वर्ष सितंबर तक 95 दिन देश के सभी राज्यों में प्रवास करेंगे और पार्टी को मज़बूती एवं पार्टी की विचारधारा को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए काम करेंगे। ज्ञात हो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती कार्य विस्तारक योजना के तहत 25 अप्रैल, 2017 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय प्रवास कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से की थी और अब अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत वे 29 अप्रैल से जम्मू-कश्मीर के प्रवास कार्यक्रम से करेंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 95 दिन के प्रवास में मुख्य फोकस संगठन विस्तार और कार्यकर्ता संवाद पर रहेगा । केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना जैसे राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष बड़े राज्यों में कम से कम तीन दिन और छोटे राज्यों में एक दिन का प्रवास करेंगे, ताकि पूरे राज्य को कवर किया जा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रवास के दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाक़ात करेंगे और संगठन के विस्तार की रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही, वे इन राज्यों में पार्टी की प्रगति और विभिन्न मोर्चे एवं गठित विभागों की कार्ययोजना (विभागों की कार्य-सूची इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है), कार्यालय निर्माण, कार्यालयों के आधुनिकीकरण, ई-लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन, बूथ स्तर पर पार्टी के निर्धारित कार्यक्रमों, कोर कमिटी के गठन व बैठकों आदि की समीक्षा भी करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर पर पार्टी की मज़बूती और पार्टी की विचारधारा को जन-स्वीकृति दिलाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल-मंत्र पर चलते हुए चलाये जा रहे गरीब-कल्याण योजनाओं को भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

विभिन्न राज्यों में अपने 95 दिन के प्रवास के दौरान माननीय अध्यक्ष जी स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन की रूप-रेखा तैयार करने में भी कार्यकर्ताओं को सुझाव देंगे। वे संगठन को मजबूत करने और पार्टी के विस्तार के कार्यक्रमों पर चर्चा करने के साथ-साथ हर राज्य के स्थानीय नेताओं से मिलकर वहां के समीकरणों को समझते हुए राज्य में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। अपने इस प्रवास कार्यक्रम के दौरान माननीय अध्यक्ष जी बुद्धिजीवियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के प्रतिष्ठित लोगों से भी रू-ब-रू होंगे और विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी को मिली अभूतपूर्व जीत के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा था कि देश में भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल आना अभी बाकी है और यह तभी संभव होगा जब भाजपा बंगाल, केरल और ओडिशा जैसे राज्यों में जीत हासिल करेगी और देश के हर कोने में हमारी विचारधारा पहुंचेगी। उन्होंने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से आलस्य छोड़ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी स्तर पर कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तारक योजना के अंतर्गत साढ़े तीन लाख पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्णकालिक के रूप में 15 दिन, 6 महीने और एक साल के लिए बूथ-स्तर पर पार्टी की मज़बूती और संगठन के विस्तार के लिए देना तय किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद भी इस योजना के तहत पूर्णकालिक के रूप में 15 दिन पांच राज्यों के लिए देना तय किया है। इसकी शुरुआत वे विगत 25 अप्रैल, 2017 से पश्चिम बंगाल से कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तीन दिवसीय बूथ प्रवास कार्यक्रम को अपार सफलता प्राप्त हुई है और कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हुआ है। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त वे केरल, ओडिशा, गुजरात और लक्षद्वीप में तीन-तीन दिन का प्रवास करेंगे और बूथ स्तर पर पार्टी की मज़बूती के लिए काम करेंगे। ■

मंगल पाण्डेय बने हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रभारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 7 मई को श्री मंगल पाण्डेय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार को हिमाचल प्रदेश भाजपा संगठन का प्रभारी नियुक्त किया। यह नियुक्ति श्रीकांत शर्मा जी के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के पश्चात रिक्त हुए स्थान पर की गयी है।

भू सम्पदा अधिनियम एक मई से प्रभावी

नौ वर्ष से लम्बित भू सम्पदा क्षेत्र का नियमन एक मई 2017 से भू सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 प्रभावी होने के साथ ही एक वास्तविकता बन गया। इसके अंतर्गत देशभर में 76,000 से अधिक रीयल एस्टेट कम्पनियों को अपनी परियोजनाएं पंजीकृत करानी होंगी। अब अधिनियम की सभी 92 धाराएं लागू हो गईं। विकासकों को वे सभी जारी परियोजनाएं और नई परियोजनाएं 3 महीने के भीतर यानी आगामी जुलाई माह के अंत तक नियामक प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत करानी होंगी, जिनके लिए अभी तक कम्प्लीशन सर्टिफिकेट यानी निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इससे मकान खरीदने वालों को अपने अधिकार हासिल करने और पंजीकरण के बाद अपनी शिकायतों का निवारण करवाने में मदद मिलेगी।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट में कहा, "भू सम्पदा अधिनियम 9 वर्ष के इंतजार के बाद लागू हो रहा है, जिससे भवन खरीदार सम्राट बन सकेगा और इससे एक नए युग की शुरुआत होगी। इससे क्रेताओं का बाजार में विश्वास बढ़ने से विकासकों को भी लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत दिलचस्पी के कारण यह अधिनियम एक वास्तविकता बन पाया है। इस अधिनियम की बदौलत रीयल्टी क्षेत्र में वांछित जवाबदेही, पारदर्शिता और सक्षमता आएगी। अधिनियम में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों के अधिकार और दायित्व परिभाषित किए गए हैं। सरकार ने इस कानून को अमली जामा पहनाने के प्रयास किए, जिनकी बदौलत यह अंततः लागू हो पाया।"

अधिनियम के प्रभावी होने से पहले आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मॉडल भू सम्पदा विनियम तैयार किए और उन्हें प्रचारित किया, ताकि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में नियामक प्राधिकरण उन्हें अपना सकें। इन विनियमों के अंतर्गत भवन निर्माताओं को अपनी अनुमोदित योजनाएं और नक्शे कम से कम तीन फुट X दो फुट के कागज पर सभी विपणन कार्यालयों में उपलब्ध कराने होंगे।

परियोजनाओं के पंजीकरण के अलावा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में निम्नांकित शामिल हैः-

- *भवन निर्माताओं को नई परियोजनाओं के मामले में खरीदारों से प्राप्त निधि का 70% हिस्सा और पहले से जारी परियोजनाओं के मामले में खर्च न की गई राशि का 70% पृथक बैंक खाते में जमा कराना होगा।*
- *न्यूनतम 500 वर्ग मीटर आकार के प्लाट अथवा 8 अपार्टमेंट्स तक के निर्माण कार्यों को नियामक प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत कराया जाएगा।*
- *विलम्ब के मामले में भवन निर्माता और क्रेता दोनों को भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल उधारी दर + 2 प्रतिशत दंड ब्याज का भुगतान करना होगा।*

- *भवन निर्माता को ढांचागत खराबी के लिए 5 वर्ष की गारंटी देनी होगी।*
- *अपील न्यायाधिकरणों और नियामक प्राधिकरणों के आदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में भवन निर्माताओं को 3 वर्ष और एजेंटों तथा क्रेताओं को एक वर्ष तक कारावास की सजा होगी।*

भू सम्पदा अधिनियम 9 वर्ष के इंतजार के बाद लागू हो रहा है, जिससे भवन खरीदार सम्राट बन सकेगा और इससे एक नए युग की शुरुआत होगी। इससे क्रेताओं का बाजार में विश्वास बढ़ने से विकासकों को भी लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत दिलचस्पी के कारण यह अधिनियम एक वास्तविकता बन पाया है। इस अधिनियम की बदौलत रीयल्टी क्षेत्र में वांछित जवाबदेही, पारदर्शिता और सक्षमता आएगी। अधिनियम में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों के अधिकार और दायित्व परिभाषित किए गए हैं। सरकार ने इस कानून को अमली जामा पहनाने के प्रयास किए, जिनकी बदौलत यह अंततः लागू हो पाया।

गौरतलब है कि यह विधेयक सबसे पहले 2013 में राज्य सभा में पेश किया गया था। उसके बाद से आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने कई दौर के विचार विमर्श के दौरान भू सम्पदा विधेयक में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और इसे पारित होने से पहले अत्यंत कारगर बनाया गया। ■

माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज फेसिलीटेशन काउंसिल पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ

केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू ने 27 अप्रैल को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय दो महत्वपूर्ण पहलों यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फेसिलिटेशन काउंसिल (एमएसईएफसी) पोर्टल और माईएमएसएमई मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र और राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

श्री कलराज मिश्र ने कहा कि http://msefc.msme.gov.in पर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फेसिलिटेशन काउंसिल (एमएसईसीसी) पोर्टल एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के विलंबित भुगतान के प्रावधानों को लागू करने में मदद करेगा तथा विलंबित भुगतान के मामलों की निगरानी में भी सहायता करेगा। इस मंच पर पहुंच से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान संबंधी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में मदद मिलेगी। दर्ज की गई शिकायतें ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से संबंध पार्टियों को भेज दी जाएंगी। इससे एमएसएमई मंत्रालय के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों को राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भी हुई प्रगति की निगरानी करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने यह भी बताया कि अधिकांश राज्यों ने पहले ही विलंबित भुगतान के मामलों से संबंधित जानकारी एमएसईएफसी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। 31.03.2017 के अनुसार 1660 करोड़ रुपये की राशि के 3690 मामलों पर विभिन्न एमएसईएफसी द्वारा विचार किया जा रहा है। वास्तव में यह ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट-अप्स की बड़ी मदद करेगा, क्योंकि विलंबित भुगतान स्टार्ट-अप्स के लिए सबसे बड़ी समस्या है।

इसके अलावा http://my.msme.gov.in पर MyMSME पर मोबाइल ऐप की भी श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा शुरूआत की गई है जो एक ही स्थान पर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एमएसएमई इकाइयां हमेशा यह शिकायत रहती थी कि सभी योजनाओं के बारे में जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं हो रही हैं। माईएमएसएमई मोबाइल एप की सहायता से इस मंत्रालय द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं के बारे में एकल खिड़की पर जानकारी उपलब्ध होगी।

एमएसएमई इस एप के माध्यम से मंत्रालय से संबंधित शिकायतों को भी दर्ज करा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस समारोह के अवसर पर ई-गवर्नेंस से एम-गवर्नेंस (मोबाइल गवर्नेंस) की ओर आगे बढ़ने की जरूरत के बारे में बात की है। इस मोबाइल ऐप ने एमएसएमई सेक्टर को एम-गवर्नेंस के युग में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाया है। ■

राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के तहत देशभर में 21 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गईं

भारत सरकार के राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम (एसएलएनपी) के अंतर्गत देशभर में 21 लाख से अधिक पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। नई लाइट से सड़कों पर अधिक रोशनी हुई है और निवासियों और वाहन चालकों के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ी है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक ऊर्जा सेवा कंपनी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) एसएलएनपी की कार्यान्वयन एजेंसी है।

एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने से सालाना 295 मिलियन इकाई किलोवॉट-ऑवर (केडब्ल्यूएच) बिजली की बचत हुई है और 2.3 लाख टन कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ है। यह परियोजना 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। इसके बाद से सड़कों पर रोशनी का स्तर काफी बढ़ा है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और गोवा में सबसे अधिक पारंपरिक लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट लगाई गई हैं। गौरतलब है कि ईईएसएल विशेष विरासत लाइटिंग परियोजना भी कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र में 1000 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और इनके अलावा 4000 अतिरिक्त लाइटें लगाई जा रही हैं। ■

प्रधानमंत्री ने किया क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में 27 अप्रैल को बहुप्रतीक्षित 'उड़ान' योजना के तहत शिमला-दिल्ली मार्ग पर पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत शिमला, नांदेड़ और कडप्पा हवाईअड्डे से उड़ानें शुरू हो गईं हैं। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर एक ई-पट्टिका का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने शिमला हवाईअड्डे पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान नांदेड़ एवं कडप्पा भी वीडियो लिंक के जरिए जुड़े हुए थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहा है। उनकी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सही अवसर मिलने पर वे चमत्कार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विमानन क्षेत्र संभावनाओं से भरा हुआ है। उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र को कभी कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर समझा जाता था, लेकिन अब यह बदल गया है। उन्होंने कहा कि नई नागरिक उड्डयन नीति भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के शहर अब विकास का इंजन बन रहे हैं और इनके बीच हवाई संपर्क का बढ़ाना लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए मददगार साबित होगी।

श्री मोदी ने कहा कि ये सफर ऐसी है जो समय भी बचाएगी और इसका खर्च टैक्सी में अगर किलोमीटर का दस रुपया लगता है तो नई पालिसी के तहत हवाई यात्रा का किलोमीटर का खर्चा सिर्फ छः या सात रुपया लगेगा। नांदेड़ से आज हैदाराबाद शुरू हो रहा है लेकिन नांदेड़ से मुंबई इसके बाद शुरू होने वाली व्यवस्था है और मैं एविएशन कंपनियों को एक सीख देना चाहता हूं। अगर एविएशन कंपनियां व्यापरिक दृष्टि से सोचते है तो सोचे कि नांदेड़ साहिब,

अमृतसर साहिब और पटना साहिब अगर हवाई सर्कुलर रूट बनाएगें तो दुनिया भर के सिख यात्री इस हवाई यात्रा का सबसे ज्यादा लाभ उठाएगें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वायु शक्ति और जल शक्ति आज के विकास के अंदर बहुत बड़ी ताकत बनते हैं और जो हम नए भारत का सपना देख रहे हें जिसमें जन-धन का सामर्थ्य है, वन-धन का सामर्थ्य है, जल-धन का भी उतना ही सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को लेकर के हमें आगे बढ़ना है।

दरअसल,'उड़ान' योजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) पर केंद्रित है। यह देश के छोटे व मझोले कस्बों को बड़े नगरों तथा परस्पर किफायती हवाई यातायात सुविधा से जोड़ने की स्कीम है। इसके तहत 500 किमी की विमान यात्रा के लिए 2500 रुपये का किराया है। इसके तहत फिक्स विंग विमानों के मामले में यात्रा की अवधि अधिकतम एक घंटे तथा हेलीकॉप्टर के मामले में आधा घंटे मानी गई है। ■

अग्रिम राशि के लिए ईपीएफ सदस्यों को अब स्व घोषणा पत्र पर्याप्त

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्यों को अब अपने सदस्यों/आश्रितों की बीमारी के मामले में अग्रिम राशि लेने के लिए केवल स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग सदस्य भी स्व घोषणा पत्र के आधार पर अग्रिम राशि ले सकते हैं। किसी भी सदस्य को अब ईपीएफ योजना-1952 के अनुच्छेद 68-जे या 68-एन के अंतर्गत अग्रिम राशि पाने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज या प्रोफार्मा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अनुच्छेद 68-जे और 68-एन में संशोधन कर दिया है और यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा। इसके अनुसार ईपीएफ के सदस्य को अपने सदस्यों/आश्रितों की बीमारी के मामले में ईपीएफ योजना के अंतर्गत अग्रिम राशि पाने के लिए केवल स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा और दिव्यांग सदस्यों के मामले में भी यह लागू होगा। इस प्रावधान को समग्र दावा फार्म में पहले ही शामिल कर दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अपने ई गवर्नेंस सुधारों के अगले चरण के हिस्से के रूप में की गई पहलों के अनुरूप ही यह प्रयास ईपीएफओ के हितधारकों को कुशलता और पारदर्शी तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य से किया जा रहा है। ■

कांग्रेस बनाम जनसंघ

– दीनदयाल उपाध्याय

(गतांक में प्रकाशित लेख का दूसरा एवं अंतिम भाग)

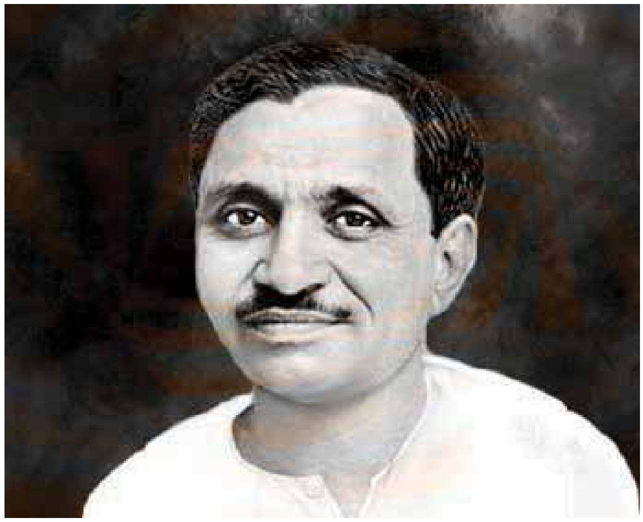

हमारी तीसरी मर्यादा धर्म की है। धर्म मज़हब नहीं है वरन् उससे ऊपर है। सहिष्णुता का सिद्धांत हम सदैव से मानते हैं। हम मजहबी राज्य (पाकिस्तान की तरह) की भी कल्पना नहीं करते, न हम धर्मविहीन राज्य 'सेक्यूलर' को समझ सकते हैं। हमारी इस मर्यादा के अनुसार प्रत्येक को अपने धर्म को मानने का अधिकार होगा, किंतु राज्य 'न्याय' का होगा। आज धर्मविहीन राज्य का नारा लगाने वाले नैतिकता तक को लोगों के ह्रदयों से निकाल दे रहे हैं, जो बहुत घातक है। देश की सभी समस्याओं का हल आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टि से बहुत सरलता से हो सकता है और महान् कार्य इसी प्रेरणा से हुए भी हैं। स्वतंत्रता का भी आदोलन तब तक जोर नहीं पकड़ सका, जब तक उसमें आध्यात्मिकता नहीं आई। हम सब मर्यादा की रक्षा करना चाहते हैं।

जनसंघ केवल सुरक्षा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। शेष सभी उद्योग वह व्यक्तियों के हाथों में सौंप देना चाहता है किंतु वह इस बात का ध्यान रखेगा कि वे पूंजीपति बनकर अपने हाथ में व्यापार का एकाधिकार न कर लें। साथ-ही-साथ आज की पूंजी की कमी को दूर करने के लिए जिसकी कि बड़े-बड़े उद्योगों में आवश्यकता है हम कुटीर उद्योग धंधों का विकास करना चाहते हैं, जिसमें कि थोड़ी पूँजी में काम चल सकेगा और पूंजीपतियों को आश्वासन देने से भी मुक्ति मिल सकेगी। साथ-ही-साथ कुटीर धंधों के विकास से हम अपनी बेकारी की समस्या को भी दूर कर सकेंगे।

भारतीय जनसंघ विरोध के लिए विरोध नहीं करता। वह एक रचनात्मक कार्यक्रम लेकर आगे आया है और इसलिए उसे जनता का सहयोग अवश्य प्राप्त होगा।

पांच वर्ष के अंदर देश में जो कार्य किया है, उसके लिए कांग्रेस वोट नहीं माँगती। कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित नेहरू ने सोचा कि पिछले चुनावों में जब हमारी सरकार बनी थी तो हम देश के अंदर एक तूफान अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करते थे और उस तूफान के उठने पर ही हमारी सरकारें बनती थीं। आज भी उन्होंने सलाह दी अपने कार्यकर्ताओं को देश के अंदर तूफान पैदा करने के लिए। वह तूफान देश में सांप्रदायिकता के विरोध में करने के लिए सलाह दी, न कि वे अगले पांच वर्ष क्या करने वाले हैं, इस पर विचार के लिए। पंडित नेहरू केवल धमकियों और विरोध को छोड़कर रचनात्मक कार्य नहीं रख सकते। परंतु पंडित नेहरू को समझना चाहिए कि तूफान पैदा करने के लिए देश के पत्ते-पत्ते को हिलाना पड़ेगा। देश की 35 करोड़ जनता के ह्रदय में तूफान उत्पन्न करना पड़ेगा। केवल ताड़ के दो पत्तों के हिलने से तूफान नहीं आ सकता। यदि यही वे करना चाहते हैं तो उन्हें राम, गुरु गोविंद सिंह, रहीम, रसखान, शिवाजी के विरुद्ध तूफान उत्पन्न करना पड़ेगा।

मुसलमान कांग्रेस रूपी उस नाव में न बैठें, जिसमें छेद हो गया है। जिस नाव को हिंदुओं ने अपना खून देकर बनाया था, उस नाव को डुबोने के लिए अब वे ही तैयार हैं। अतः उसके साथ चलने में मुसलमानों को कोई फायदा नहीं।

श्री टंडनजी को आज के ही कांग्रेसियों ने अपना नेता बनाया था, परंतु चुनाव जीतने के लिए उन्हें लातों से मार दिया। तो जो लोग अपने नेता को चुनाव जीतने के लिए ठुकरा देते हैं, वे ही चुनाव जीतने पर मुसलमानों को भी ठुकरा देंगे।

देश के प्रति जो गद्दारी करेगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। पंडित नेहरू का विरोध भी हम इसलिए करते हैं कि वे अंग्रेजियत को बनाए रखना चाहते हैं, जो देश के लिए हितकर नहीं है। संस्कृति किसी मजहब की नहीं होती, देश की होती है। यदि मज़हब की संस्कृति होती तो अरब, फारस आदि की एक संस्कृति होती, परंतु ऐसा नहीं है। हिंदुस्थान के मुसलमान यदि राम-कृष्ण को अपना आदर्श मानते, गंगा-जमुना को अपनी पवित्र नदी मानते हैं तो उनका मजहब खतरे में नहीं पड़ जाता। महाकवि रहीम, रसखान तो मुसलमान ही थे, परंतु इस देश का वे गुणगान करते रहे तो हमने कभी नहीं कहा कि उनको हिंदी साहित्य से निकाल दिया जाए। अपितु उनका आदर किया। हम चाहते हैं कि हमारे देश के मुसलमान रहीम बनकर रहें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी रक्षा, उनका उत्थान भारत की तैंतीस कोटि जनता हमेशा करेगी। ■ (समाप्त)

(पांचजन्य, जनवरी ३, १९५२)

नहीं रहे विनोद खन्ना

भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता श्री विनोद खन्ना का निधन 27 अप्रैल को हो गया। वे 70 साल के थे। श्री खन्ना बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विख्यात फिल्म अभिनेता, सांसद, विदेश राज्य मंत्री एवं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री थे। श्री खन्ना के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, "एक मशहूर कलाकार, प्रतिबद्ध नेता और बेहतरीन इंसान के तौर पर मैं विनोद खन्ना को हमेशा याद रखूंगा। उनके निधन से गहरा दुख पहुंचा है। मेरी श्रद्धांजलि।"

6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में जन्मे श्री विनोद खन्ना ने 140 से भी ज्यादा फ़िल्मों में अभिनय किया। करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने सहायक अभिनेता और खलनायक के किरदारों में काम किया। उनकी फिल्मों को बहुत सराहा गया और उनके प्रशंसकों की बहुत बड़ी संख्या है। मेरा गांव मेरा देश, जेल यात्रा, मुकदर का सिकंदर, इंकार, अमर अकबर एंथनी, राजपूत, कुर्बानी, खुदरत और दयावान उनकी यादगार फिल्मे हैं, जिनमें किये गये उनके अभियन को लोग हमेशा याद रखेंगे।

1997 में श्री विनोद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और पंजाब की गुरदासपुर सीट से चार बार लोकसभा सांसद रहे। उन्होंने 1998, 1999, 2004 और 2014 का लोकसभा चुनाव जीता। श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्होंने पर्यटन और संस्कृति मंत्री के तौर पर काम किया। बाद में उन्हें विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू ने प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार और सांसद श्री विनोद खन्ना के निधन पर शोक व्यक्त किया। शोक संतप्त परिवार को भेजे अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि प्रसिद्ध फिल्म हस्ती और सांसद (गुरदासपुर से) श्री विनोद खन्ना के असामयिक निधन से उन्हें बहुत दुःख हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भारतीय सिनेमा में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके असामयिक निधन से हुई क्षति को पूरा करना बहुत कठिन है।

उन्होंने कहा कि श्री विनोद खन्ना भारतीय जनता पार्टी से पिछले 20 वर्षों से जुड़े रहे। श्री वाजपेयी जी की सरकार में वे केन्द्रीय मंत्री भी रहे। वर्तमान में गुरदासपुर से सांसद श्री खन्ना के निधन से भारतीय जनता पार्टी और गुरदासपुर की जनता को बहुत हानि पहुंची है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के सदस्यों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस ने श्री खन्ना को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "विनोद खन्ना जी हमेशा फ़िल्म इंडस्ट्री और राजनीति को दिए योगदान की वजह से जाने जाएंगे। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को भगवान दुख सहने की क्षमता दे।" ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा जारी

शोक–संदेश

मुझे जानकार यह अत्यंत दुःख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोक सभा सांसद एवं प्रसिद्ध सिने अभिनेता श्री विनोद खन्ना जी का निधन हो गया। वे एक उत्कृष्ट राजनेता, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता और बेहतरीन कलाकार थे।

बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री खन्ना चार बार लोक सभा सांसद रहे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के पद पर भी रहे। मूल्य आधारित राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे श्री खन्ना हमेशा जनता के मुद्दों से जुड़े रहे और संसद में उनकी समस्याओं को उठाते रहे।

एक शानदार अभिनेता के साथ-साथ सौम्य व्यक्तित्त्व, ओजस्वी वक्ता, जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाने वाले एक जुझारू नेता के रूप में श्री खन्ना सदैव याद किये जायेंगे। उनके निधन से न केवल कला जगत ने एक बेहतरीन अभिनेता और अच्छे व्यक्तित्व को खो दिया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह एक अपूरणीय क्षति है। एक उत्कृष्ट अभिनेता और सांसद के रूप में किये गए उत्कृष्ट कार्य के माध्यम से वे हमेशा हमारे दिलों पर राज करते रहेगे।

दुःख की इस घड़ी में मैं स्वयं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनके परिवार और उनके लाखों प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उज्ज्वला से उजाला

उज्ज्वला - गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन और उज्ज्वला से उजाला के तहत सौर प्रकाश व्यवस्था पूरे आतंरिक इलाके को जगमग कर रही है तथा विशेष रूप से महिलाओं को खुश कर रही हैं। इससे बिजली की दरें और व्यापारिक लागतें कम हो रही हैं। मोदी सरकार के तीन सालों को एक नए युग की शुरूआत के रूप में देखा जा रहा है, जो पद दलितों की उम्मीदों और अवसरों को ऊंचा उठा रहा है।

| शिवाजी सरकार |

श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का एक अपना अनोखा रिकॉर्ड है। इसका तीन साल का कार्यकाल घोटाला मुक्त है।

अभी तक किसी भी गलती का पता लगाने वाले व्यक्ति के लिए इसके दामन में कोई दाग खोजना बड़ा मुश्किल काम रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी शासन व्यवस्था का प्रबंधन करना कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन इस तंत्र में सच्चाई लाने के संकल्प ने जाहिरा तौर पर कीमत अदा की है।

सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों ने घोटालेबाजों के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है। विभिन्न देशों के साथ किए गए अनेक समझौतों ने मॉरीशस, साइप्रस और सिंगापुर से होकर गुजरने वाले काले धन के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया हैं। हालांकि मॉरीशस, सिंगापुर और साइप्रस मार्गों के माध्यम से पहले लॉन्डरिंग किए जा चुके धन को अब भारत में वापस नहीं लाया जा सकता है।

सरकार ने स्विट्जरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों के साथ वास्तविक समय लेनदेन डेटा अनुबंध किया है। यह अनुबंध सितंबर 2019 से भारत से स्विस बैंकों के साथ हुए किसी भी लेनदेन से संबंधित जानकारी को साझा करना सुनिश्चित करता है। यह मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को भी रोकता है।

सरकार ने विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) को लागू करने के लिए अमेरिका के साथ अंतर-सरकारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये सभी अनुबंध स्वतः ही विदेशों से भारतीय लोगों के वित्तीय खातों की जानकारी प्राप्त करने में भारतीय कर अधिकारियों को सक्षम बनाते हैं।

गलत तरीके से कमाया धन या कर-चोरी से की गई बचत अब एक व्यापक और निवारक कानून काला धन, अघोषित विदेशी परिसंपत्तियां तथा कर अधिरोपण अधिनियम के तहत आ गई हैं। इस अधिनियम में कठोर दंड और मुकदमा चलाने का प्रावधान है।

केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने 2 जुलाई, 2016 को कहा था कि आयकर विभाग ने 2014 से 2016 के बीच जांच पड़ताल के माध्यम से 43,000 करोड़ रूपये की अघोषित आय का पता लगाया है।

अभी तक की सबसे बड़ी आय (काला धन) घोषणा 2016 में एक

मुश्त अनुपालन खिड़की में कम से कम 65,250 करोड़ रूपये की अघोषित परिसंपत्तियां की घोषणाएं की गई थीं, जिससे सरकार को करों के रूप में 29,362 करोड़ रुपये की आमदनी हुई।

बेनामी लेनदेन कानून न केवल बेनामी संपत्तियों को भी लक्षित करता है बल्कि ऐसी संपत्तियों को रखने की भी रोकथाम करता है। यह कानून 18 साल पहले बनाया गया था, लेकिन यह मोदी सरकार द्वारा कार्यान्वयन करने के लिए 1 नवंबर, 2016 तक इंतजार करता रहा। बेनामी लेनदेन को अवैध कमाई खपाने का एक सबसे बड़ा मार्ग बताया जाता था। इस कड़े कानून को प्रवर्तन निदेशालय के रूप में कठोरता से लागू किया जा रहा है और आयकर विभाग ने इस प्रणाली को साफ करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

विभिन्न खनिज ब्लॉकों का नीलामी के माध्यम से आवंटन किया गया है जिससे गतिविज्ञान ही बदल गया है। कोयला ब्लॉकों, स्पेक्ट्रम और खनिजों की ऑनलाइन नीलामी के मानदंड के अनुसार की गई है। भविष्य में किसी भी सरकार के लिए इसमें बदलाव करना आसान नहीं होगा।

वह शासक संदेह से ऊपर है, जिसने राजनीतिक वित्तपोषण को एक मुश्किल प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया है। कुछ छोटी पार्टियों ने इस मार्ग को अवैध धन जुटाने का मार्ग बना लिया था। राजनीतिक वित्त पोषण के नए नियम में नकद प्राप्ति की सीमा को घटाकर 2000 रूपये कर दिया गया है। चुनाव बांड की शुरूआत का उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों के वित्तपोषण की सफाई करना है।

सफाई की यह प्रक्रिया उसी दिन शुरू हो गई थी जब श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। जिस दिन नई सरकार ने पद ग्रहण किया था उसी दिन इसने भ्रष्टाचार के मामले पर गौर करने के लिए उच्चतम न्यायालय की देखरेख में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

प्रधानमंत्री देश में ही अवैध धन के खिलाफ निशाना साधने तक ही सीमित रहें बल्कि प्रधानमंत्री ने 5 सितंबर, 2016 को महत्वपूर्ण जी-20 की बैठक में यूरोप और अन्य देशों में बन गए सुरक्षित कर शरण स्थलों के मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से उठाया था। इसने प्रमुख जी-20 देशों को मनीलॉन्ड्रिंग, काले धन और आतंक वित्तपोषण के विरूद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर किया।

यह संभवतः सिर्फ शुरुआत ही थी। सभी कार्यवाहियों की जननी 8 नवंबर, 2016 को 8 बजे सांय सामने आई थी। प्रधानमंत्री ने काले धन को कोठरी से बाहर निकालने के लिए 15 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण करने की घोषणा की। इससे देश में उतेजना फैल गई और बैंकों के सामने नोट बदलने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। लोगों ने सफाई के उद्देश्य के लिए परेशानियां भी झेली।

आयकर विभाग ने ऐसे 18 लाख लोगों की पहचान की है, जिन्होंने तथाकथित बेहिसाबी राशियां जमा कराईं जिन्हें इसका ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। यहां तक कि जन-धन जैसे खातों का भी धन जमा करने के लिए भी उपयोग किया गया।

एनडीए सरकार के इन प्रयासों की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों द्वारा प्रशंसा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अब भारत को व्यापार करने के लिए एक बेहतर स्थान के रूप में देख रहा है। 4 मई, 2017 को एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने वस्तु और सेवा कर अधिनियम को लागू करने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की सराहना की और कहा कि इससे देश में अप्रत्यक्ष कर और दिवालियापन अधिनियम एकीकृत होंगे। एडीबी अध्यक्ष टेकहिको नकाओ का कहना है कि इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत और अगले वर्ष 7.6 प्रतिशत की दर से विकास करेगी और इससे देश में बेहतर कारोबार के अनुकूल वातावरण पैदा होगा।

एनडीए सरकार के अनेक प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ है कि भारत, चीन को पीछे छोड़कर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और देश में व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुकूल वातावरण कायम हुआ है।

सफाई की यह प्रक्रिया उसी दिन शुरू हो गई थी जब श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। जिस दिन नई सरकार ने पद ग्रहण किया था उसी दिन इसने भ्रष्टाचार के मामले पर गौर करने के लिए उच्चतम न्यायालय की देखरेख में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

वास्तव में अपने कार्यकाल की शुरुआत में सरकार ने कदाचारी और अक्षम कल्याणकारी वितरण प्रणाली को हटाना सुनिश्चित कर लिया था। सरकार ने अपने प्रतिष्ठापन के रूप में जैम (जनधन, आधार और मोबाइल) के साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की शुरूआत की थी। इसने 65 मंत्रालयों और विभागों में 536 योजनाओं को लक्षित किया था। उज्ज्वला - गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन और उज्ज्वला से उजाला के तहत सौर प्रकाश व्यवस्था पूरे आतंरिक इलाके को जगमग कर रही है तथा विशेष रूप से महिलाओं को खुश कर रही हैं। इससे बिजली की दरें और व्यापारिक लागतें कम हो रही हैं। मोदी सरकार के तीन सालों को एक नए युग की शुरूआत के रूप में देखा जा रहा है, जो पद दलितों की उम्मीदों और अवसरों को ऊंचा उठा रहा है। ■

भारतीय संदर्भ में विकास की संकल्पना

| डॉ० शिव शक्ति बक्सी |

जनसंघ विचारक पं. दीनदयाल उपाध्याय ने 1958 में अपनी पुस्तक 'द टू प्लांस : प्रॉमिसेस, परफॉर्मेंसेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स' में पंचवर्षीय योजनाओं पर शंका जाहिर की और कहा कि केंद्रीकृत आर्थिक योजनाएं लोकतंत्र के अनुरूप होनी चाहिए और योजनाओं का मूल सामाजिक अर्थशास्त्र पर आधारित हो। देश के वार्षिक बजट और तत्कालीन योजनाओं के बीच संबंधों जांच–पड़ताल के बाद उनका विचार था कि भारतीय समस्याओं का वास्तविक समाधान पश्चिमी देशों द्वारा विकसित किए गए राजनैतिक और आर्थिक मॉडल में शायद ही संभव हो। उनका विचार था कि देश का नया विकास मॉडल भारतीय वास्तविकता से मेल खाता हो, लेकिन ऐसा न हो सका। नेहरू ने विकास का ऐसा मॉडल विकसित किया, जो भारतीय परम्परा के अनुरूप न होकर पश्चिम द्वारा विकसित किए गए मॉडल से ज्यादा प्रभावित था। विकास का यह मॉडल कई दशकों तक प्रभावी रहा, जिसके कारण देश का वह विकास नहीं हो सका, जिसकी उम्मीद लोगों को थी। देश में गरीबी, अशिक्षा आदि का बोलबाला तो था ही, साथ ही तीव्र विकास के लिए

नीति आयोग का उद्देश्य है कि व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाओं की निर्माण प्रक्रिया भारतीय वास्तविकता के दायरे में हो। नीति आयोग का कार्य तीन वर्षीय कार्य एजेण्डा (टीवाईएए), सप्तवर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय दृष्टिपत्र का निर्माण करके देश के लिए वैकल्पिक आर्थिक संकल्पना प्रस्तुत करना है। यह अभी तक चली आ रही पश्चिम के आर्थिक मॉडल से प्रभावित नेहरूकी अर्थ संरचना से बिल्कुल अलग है।

जरूरी बिजली, सड़क और परिवहन जैसी आधारभूत संरचनाओं का समुचित विकास न हो सका। सच तो यह है कि योजना आयोग एक कर्मकांडी सरकारी संस्था बनकर रह गया। अंततः 2017 में 12वीं

पंचवर्षीय योजना का औपचारिक अंत हो गया। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ।

नीति आयोग का उद्देश्य है कि व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाओं की निर्माण प्रक्रिया भारतीय वास्तविकता के दायरे में हो। नीति आयोग का कार्य तीन वर्षीय कार्य एजेण्डा (टीवाईएए), सप्तवर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय दृष्टिपत्र का निर्माण करके देश के लिए वैकल्पिक आर्थिक संकल्पना प्रस्तुत करना है। यह अभी तक चली आ रही पश्चिम के आर्थिक मॉडल से प्रभावित नेहरू की अर्थ संरचना से बिल्कुल अलग है। दरअसल, नीति आयोग वर्ष 2017–18 और 2019–20 की अवधि के लिए नई नीति निर्माण हेतु टीवाईएए डाक्यूमेंट लेकर आया। यह दस्तावेज वर्तमान में प्रक्रियागत सप्तवर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय दृष्टिपत्र की एक कड़ी है। व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु टीवाईएए में एक नई दृष्टि है। दस्तावेज 7 भागों और 24 अध्यायों में विभाजित है। यह वर्तमान संदर्भों में विकास की संकल्पना प्रस्तुत करता है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ–साथ यह कृषि, उद्योग और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को दुगुनी करना और उद्योगों और सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण रोजगार का निर्माण करना है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास करना भी इसका लक्ष्य है। टीवाईएए का ध्यान ग्रामीण भारत में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी है। साथ ही नई रणनीति का निर्माण कर शहरी विकास पर भी काफी जोर दिया गया है। दस्तावेज में देश के विकास को बढ़ावा देने वाले अन्य कई महत्वपूर्ण बिन्दु भी हैं, जैसे–परिवहन, डिजिटल कनेक्टिविटी, पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप, ऊर्जा, विज्ञान व तकनीक और उद्यमशीलता। समावेशी समाज के निर्माण में टीवाईएए स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के महत्व को स्वीकार करता है। यह कर–प्रणाली, प्रतिस्पर्धा, कानून के शासन के साथ–साथ न्यायपालिका व पुलिस में व्यापक सुधार तथा कानून व व्यवस्था व अन्य अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है। टीवाईएए व्यापक

स्थायी विकास की बात तो करता ही है, साथ ही यह पर्यावरण, वन और जल–प्रबंधन जैसे संवेदनशील मुद्दों की अनदेखी नहीं करता।

2022–23 तक किसानों की आय दुगुनी करना टीवाईएए का प्रमुख लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति हेतु विस्तृत रणनीति और योजनाएं तैयार की जा रही हैं। यह बात जानते हुए भी भारत की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, फिर भी कृषि को शायद ही कभी प्राथमिकता दी गई। अभी तक कृषि के विकास हेतु समुचित रणनीति और व्यावहारिक नीतियों का अभाव था। यद्यपि कृषि राज्य का विषय है, परन्तु वर्तमान अनुमान के अनुसार लगभग 45.7 प्रतिशत लोग का जीवन इस पर निर्भर है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय योजनाओं के द्वारा इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाये। कृषि उत्पाद के आवागमन एवं विपणन जैसे अनेक विषयों जो विभिन्न राज्यों के सीमाओं से बंधे नहीं हैं, उसमें प्रभावी तालमेल एवं समायोजन की आवश्यकता रहती है। किसान अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करें, इसके लिये भी आवश्यक है वर्तमान कृषि विपणन व्यवस्था एवं सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम सटीक मूल्य

2022–23 तक किसानों की आय दुगुनी करना टीवाईएए का प्रमुख लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति हेतु विस्तृत रणनीति और योजनाएं तैयार की जा रही हैं। यह बात जानते हुए भी भारत की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, फिर भी कृषि को शायद ही कभी प्राथमिकता दी गई। सच तो यह है कि अभी तक कृषि के विकास हेतु समुचित रणनीति और व्यावहारिक नीतियों का अभाव था।

की व्यवस्था में व्यापक सुधार हो। जहां न्यूनतम खरीद मूल्य की व्यवस्था में व्यापक सुधार हो। जहां न्यूनतम खरीद मूल्य केवल कुछ उत्पादों एवं सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लागू होता है, वहीं कृषि विपणन व्यवस्था नीतिगत दोषों, बड़ी संख्या में बिचौलियों की मौजूदगी, कमजोर आधारभूत संरचना, एकीकरण तथा अधिकृत मंडियों की कमी का मार झेल रहा है। टीवाईएए ने ठीक ही कृषि उत्पाद विपणन समिति कानून तथा आवश्यक वस्तु कानून में सुधार पर जोर दिया है, साथ ही व्यवस्था को ठीक करने में ई–नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) की भूमिका को स्वीकार किया है। इन पहलों से देश में एक नई कृषि परितंत्र के निर्माण में सहायता मिलेगी।

कृषि विकास के ठहराव के संदर्भ में द्वितीय हरित क्रांति की जहां चर्चा होती है, वहीं उत्पादकता बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। एक ओर जहां भारत अनाज उत्पादन में आत्म–निर्भर दिखता है वहीं कई मायनों में विश्व स्तर की उत्पादकता प्राप्त करने का लक्ष्य अभी भी प्राप्त करना बाकी है। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक केवल 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर दूसरी फसल लगाई जाती है और कुछ राज्यों में तो यह दर भाग 25 प्रतिशत ही है। टीवाईएए सिंचाई, तकनीक, बीज तथा फल, सब्जी, दूध अण्डा, मुर्गी पालन तथा मत्स्य पालन जैसे उच्च मूल्य उत्पादों की तरफ किसानों को मोड़कर उत्पादकता में वृद्धि पर जोर देती है। एक प्रभावी सिंचाई तंत्र विकसित करने में एक्सीलेरेटेड इरीगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास कार्यक्रम प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। टीवाईएए में एक व्यावसायिक, उत्साहवर्धक, बाजारोन्मुख, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकने वाली कृषि अनुसंधान के लिए आधार तैयार करने की बात की गई है। बागवानी, दूध उत्पादन, मुर्गीपालन जैसी गतिविधियों से निश्चित रूप से किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि होगी। परम्परागत तरीके की जोत–काश्तकारी, जमीन के पट्टे के रखरखाव की समस्या के निदान पर बल तथा कृषि के लिए पट्टे पर जमीन उपलब्ध करने के नवीन प्रस्ताव से कृषि क्षेत्र में उन्नत तरीके तथा तकनीक के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में टीवाईएए ने अनेक नीतिगत पहलों से विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक व्यापक योजना में बुनने का प्रयत्न किया है। गरीबी को इसके हर रूप में समाप्त करने के भारतीय लक्ष्य को प्राप्त करने में यह दस्तावेज केवल कृषि ही नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दे रहा है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों के बिना आने वाले दो–तीन वर्षों में आठ प्रतिशत से अधिक का विकास दर प्राप्त करना आसान नहीं होगा और जबकि टीवाईएए ने इस सच्चाई को स्वीकारा है तब इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि अब देश के पास एक वैकल्पिक आर्थिक दृष्टि तथा आवश्यक नीतिगत ढांचा है। योजना के प्रति पूर्व के दृष्टिकोण से असहमत होते हुए पं0 दीनदयाल उपाध्याय का मत था कि केवल विकेंद्रित कृषि–उद्योग ग्रामीण समाज के भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो सकती है। अब भी यह देखना बाकी है कि टीवाईएए, सप्तवर्षीय रणनीति एवं पंद्रह–वर्षीय दृष्टिपत्र एक दूसरे से कितने जुड़े साबित होते हैं तथा तीनों दस्तावेज देश के सामने कृषि को प्रमुखता देते हुए किस प्रकार की समग्र दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। यदि ऐसा होता है तब इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने बड़े लक्ष्यों को प्रभावी कार्यान्वयन से प्राप्त कर सकेगी। इससे भारतीय विकास की नई अवधारणा को गढ़ने तथा वास्तविकता के धरातल से जुड़ी पहलों की तरफ कदम बढ़ाने के लिए नीति आयोग के योगदान को सराहा जाएगा। ■

(लेखक भाजपा पत्रिकाएं व प्रकाशन विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख हैं)

कांग्रेस सरकार प्रदेश का विकास नहीं कर सकती: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 मई को देश के सभी राज्यों के 95 दिवसीय विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत अपने दो दिवसीय हिमाचल प्रदेश के प्रवास के अंतिम दिन पालमपुर में प्रदेश के बुद्धिजीवियों के साथ कई विषयों पर चर्चा की और उनसे भारतीय जनता पार्टी के साथ मन से जुड़ने की अपील की। इसके पश्चात् उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद देश के वीर जवान कैप्टन सौरभ कालिया के पिताजी डॉ एन के कालिया को शाल ओढ़ा कर और पुष्प-गुच्छ देकर सम्मानित किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन सौरव कालिया तक हिमाचल की पवित्र धरती के वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जो आत्म-बलिदान की उच्च परंपरा स्थापित की है, वह हमारे लिए गौरव और श्रद्धा का विषय है। उन्होंने कहा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हिमाचल प्रदेश एक अन्य कारण से भी प्रिय है क्योंकि यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का प्रिय प्रदेश है, प्रधानमंत्री जी ने इसे बार-बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है, उन्होंने लंबे समय तक प्रदेश में संगठन का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि जन संघ से भारतीय जनता पार्टी की संगठन के विकास और राजनीतिक वैभव की जो यात्रा है, वह हमारे महान नेताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण है। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी पार्टी का अध्यक्ष हूं जिसके पास हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका कोई परिवार नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके परिवार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो भी नेता हुए हैं - डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी, श्री सुन्दर सिंह भंडारी जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, नानाजी देशमुख जी, श्री कैलाशपति मिश्र जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी और न जाने कई अन्य मनीषी और उन्हीं के त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी को आज यह स्थान प्राप्त हुआ है जिन्होंने अपने जीवन का क्षण-क्षण और शरीर का कण-कण पार्टी और संगठन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, पार्टी के सिद्धांत और पार्टी की कार्यपद्धति के कारण भी भारतीय जनता पार्टी की एक अलग प्रकार की छवि है। उन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मेरा मानना है कि यदि किसी पार्टी का मूल्यांकन करना है तो उसका मूल्यांकन तीन प्रकार से हो सकता है - पहला, पार्टी का आतंरिक लोकतंत्र किस प्रकार से काम कर रहा है, दूसरा - पार्टी किस सिद्धांत पर चल रही है, और तीसरा - जनादेश मिलने के बाद पार्टी जब सरकार में आती है, तो किस प्रकार से काम करती है।

पार्टी के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करते हुए माननीय राष्ट्रीय

अध्यक्ष ने कहा कि देश में सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टियों का अकाल पड़ गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सिद्धांत से मतलब है देश के लिए बनने वाली सभी नीतियों पर पार्टी के पास स्पष्ट दृष्टिकोण का उपलब्ध होना और उस दृष्टिकोण के आधार पर देश के लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से अपना पक्ष रखना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हो या वामपंथी दल या फिर क्षेत्रीय पार्टियां – उनका कोई सिद्धांत ही नहीं है, उनके पास देश के लिए कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गठन तो देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए किया गया था, वह तो आजादी को प्राप्त करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हेकिल भर थी, उसकी कोई विचारधारा ही नहीं थी, वह कभी सिद्धांतों के आधार पर चली ही नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई विचारधाराओं वाले लोग थे और उन सब के पास कोई सिद्धांत नहीं था, केवल किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था, इसलिए बाद में इससे कई पार्टियां अलग-अलग समय पर बाहर निकलती चली गई।

श्री शाह ने कहा कि जब डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जन संघ की स्थापना की थी तो उससे पहले वे पंडित नेहरू जी की सर्वदलीय सरकार में उद्योग मंत्री थे। उन्होंने कहा कि नेहरू जी के नेतृत्व में जब देश की विकास नीति, कृषि नीति, विदेश नीति, अर्थ नीति, रक्षा नीति और शिक्षा नीति का निर्माण हो रहा था तब डॉ मुखर्जी सहित कई मनीषियों को लगा कि नेहरू सरकार देश के लिए जो नीतियां बना रही है, उन नीतियों के रास्ते पर यदि यह देश चलता रहा तो पीछे मुड़ने का भी रास्ता नहीं मिलेगा, तब उन लोगों ने एक ऐसी वैकल्पिक नीति को राष्ट्र के सामने रखने का साहस किया जिसमें देश की मिट्टी की

सुगंध हो, उससे पाश्चात्य विचारों की बू न आती हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जन संघ की विचारधारा में एक बड़ा मूल अंतर यह था कि कांग्रेस देश का नवनिर्माण करना चाहती थी जबकि भारतीय जन संघ देश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली वैभव के आधार पर देश का पुनर्निर्माण करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि देश के सामने वैकल्पिक विचारधारा प्रस्तुत करने के लिए ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जन संघ की स्थापना हुई जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज देश की जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि सिद्धांत के आधार पर देश के विकास के लिए काम करने वाली यदि कोई पार्टी आज है, तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी सिद्धांत के आधार पर नहीं चल सकती, उसका लक्ष्य कभी सही नहीं हो सकता और जिस पार्टी का लक्ष्य सही नहीं है, वह देश का कभी विकास नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो एक निश्चित सिद्धांत के आधार पर चलती है, जिसके पास देश के हर विषय, हर मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण है और इसलिए भी हम सभी पार्टियों से अलग हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद देश में 70 सालों तक जो सरकारें चली हैं उसमें से एक तो कांग्रेस की सरकार है जो लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में रही हैं, कई राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकारें भी रही हैं, कुछ समय तक केंद्र में और कई राज्यों में प्रादेशिक दलों की सरकारों ने भी शासन किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देश में केंद्र और राज्यों में चली हैं। उन्होंने कहा कि देश ने चारों प्रकार की सरकार देखी है - कांग्रेस की विचारधारा, कम्युनिस्ट की विचारधारा, परिवारवाद व जातिवाद की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर चलने वाली सरकारें देखी है। हिमाचल प्रदेश के प्रबुद्ध जनों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अब देश में तुलनात्मक अभियान करने का समय आ गया है, चारों प्रकार के विकास के मॉडल देश की जनता के सामने है, उनके विकास के आंकड़े जनता के सामने उपलब्ध हैं - यह देखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों में क्या विकास हुआ है, कम्युनिस्ट की राज्य सरकारों में कैसा विकास हुआ है, परिवारवाद व जातिवाद के आधार पर चलने वाली क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारों के राज्य में कैसा विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कैसा विकास हुआ है। उन्होंने कई राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह कांग्रेस सरकारों, कम्युनिस्ट दलों की सरकारों और क्षेत्रीय दलों की सरकारों ने राज्य के विकास को बाधित कर उसे काफी पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि जिन-जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं, वहां हमने विकास के नए मापदंड स्थापित किये और उस राज्य के इतिहास में डेवलपमेंट की नया अध्याय जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस के एक नए युग की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, वह सरकार लोकाभिमुख सरकार होती है, पारदर्शी सरकार होती है, निर्णायक सरकार होती है और लोक-कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार होती है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कई काम किये हैं। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में जहां सेन्ट्रल टैक्स में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 11131 करोड़ रुपये थी, वहीं नीति आयोग के 14वें वित्त आयोग में हिमाचल की हिस्सेदारी करीब तीन गुणा बढ़ कर 28225 करोड़ रुपये हो गयी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को भी 7889 करोड़ रुपये से लगभग छः गुणा बढ़ा कर 40625 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 25000 मेगावाट से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन करने की क्षमता वाले तीन प्रमुख परियोजनाओं की

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कारगिल युद्ध में शहीद देश के वीर जवान कैप्टन सौरभ कालिया के पिताजी डॉ. एन के कालिया को शाल ओढ़ा कर और पुष्प-गुच्छ देकर सम्मानित किया।

शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में एम्स और आईआईएम भी दिए गए हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार विकास की एक भी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में नाकाम रही है क्योंकि हिमाचल सरकार की विकास करने में कोई रुचि ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार का माफिया राज है, इससे यह स्पष्ट है कि हिमाचल की यह कांग्रेस सरकार प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब राज्य सरकार के पास विकास का विजन हो लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार तो बस राजनीति करनी है, अपने स्वार्थ के लिए सरकार चलानी है तो ऐसे में विकास की आशा कैसे की जा सकती है। ■

'माणिक सरकार ने दस हजार शिक्षकों को बेरोजगार करने का पाप किया'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 7 मई को कुमारघाट (त्रिपुरा) के फटिकरॉय पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में आयोजित विशाल जन-सभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से भ्रष्टाचारी, दमनकारी और विकास को अनदेखा करने वाली कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंक कर भारतीय जनता पार्टी की विकासोन्मुखी एवं लोक-कल्याणकारी सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं मां त्रिपुर सुन्दरी की इस पवित्र धरती को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि स्वर्ग से भी सुंदर त्रिपुरा का देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि श्री एस डी बर्मन, श्री आर डी बर्मन और श्री सोमदेव बर्मन जी ने यहां का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया है। ज्ञात हो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन विस्तार के 95 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा में थे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि रोज वैली चिटफंड घोटाले में त्रिपुरा सरकार के दिग्गज मंत्रियों का नाम आया है, राज्य के लाखों-गरीबों का पैसा रोज वैली मामले में सीपीएम के नेता चट कर गए हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक सरकार को चुनौती देता हूं - यदि आप पाकसाफ हैं, यदि आप के लोग रोज वैली चिटफंड घोटाले में लिप्त नहीं हैं, यदि आप में हिम्मत है तो आप रोज वैली चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दीजिये। उन्होंने कहा कि अगर रोज वैली चिटफंड घोटाले की जांच सही तरीके से हुई तो रोज वैली का एक-एक पैसा सीपीएम के नेताओं और कैडरों के घर से निकलेगा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की सीपीएम सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है।

श्री शाह ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं पर अत्याचार की सबसे अधिक घटनाएं त्रिपुरा में होती हैं, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछले 10 महीनों में लगभग 900 से अधिक महिलाओं के साथ छेड़खानी और दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में महिलायें सलामत नहीं होती, उस राज्य का कभी विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के लगभग 25% अर्थात् एक-चौथाई पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं और माणिक सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जो सरकार त्रिपुरा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों को अभी भी चौथे वेतन आयोग के अनुसार ही वेतन मिलता है, जबकि पूरा देश सातवें वेतन आयोग को स्वीकार कर चुका है। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में माणिक सरकार के बहुत कम दिन बचे हैं, माणिक सरकार जाने वाली है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार

बनने के बाद सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की माणिक सरकार ने 10,000 शिक्षकों को बेरोजगार करने का पाप किया है, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों की भर्ती करते वक्त सरकारी नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को निरस्त कर दिया।

कांग्रेस की यूपीए सरकार (कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित सरकार) ने 13वें वित्त आयोग के पांच वर्ष में त्रिपुरा को जहां केवल लगभग 7000 करोड़ रुपये ही दिए, वहीं मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में पांच वर्षों में त्रिपुरा को 25923 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली बार अगरतला से बांग्लादेश तक रेल लिंक का काम हुआ, राज्य में तीन विद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ, राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर के कामों में तेजी आई, यहां के आदिवासियों की खुशहाली के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये दिए गए और डोनर मंत्रालय के तहत राज्य को दी जाने वाली सहायता में 60% की बढ़ोत्तरी की गयी। उन्होंने कहा कि राज्य में सायंस सिटी के लिए 28 करोड़ रुपये दिए गए हैं ताकि इसके माध्यम से त्रिपुरा के युवा विश्व के युवाओं से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। डिग्री कॉलेजों के अपग्रेडेशन के लिए 48 करोड़ रुपये दिए गए, जीबी पंत अस्पताल के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये दिए गए, राज्य में पांच नेशनल हाइवे बनाए गए हैं, त्रिपुर सुन्दरी एक्सप्रेसवे बनाया गया है, कचरे का संयंत्र लगाने के लिए 6 करोड़ रुपये दिए गए, एयरपोर्ट के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि दी गई, लेकिन विकास का कोई काम राज्य में दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि जब तक त्रिपुरा में सीपीएम की माणिक सरकार की सरकार है, तब तक राज्य में विकास संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की जनता विकास चाहती है और इसके लिए उनके पास एक ही विकल्प है – भारतीय जनता पार्टी। ■

'भाजपा सरकार ने रिफॉर्म्स के बदले ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी कार्यपद्धति का हिस्सा बनाया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 29 अप्रैल को जम्मू (जम्मू-कश्मीर) के स्टेट गेस्ट हाउस में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से रू-ब-रू हुए और विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार की पार्टी है और जब मैं अलग प्रकार की पार्टी कहता हूं तो इसके मूल में पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के कृतित्व, परिश्रम, त्याग और बलिदान की पृष्ठभूमि है। उन्होंने कहा कि जब किसी भी पार्टी के बारे में जानना हो, जब किसी भी पार्टी को समझना हो तो उस पार्टी की स्थापना के मूल में जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने देश को आगे ले जाने के लिए आजादी के बाद हमने केंद्र हो या राज्य, हर जगह हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं, बल्कि मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकार किया है, बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को स्वीकार किया है और इस तरह हमारे लोकतंत्र में पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर हमें इस बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को सही तरीके से आगे ले जाना है तो किसी एक पार्टी में चार गुण होना बहुत जरूरी है - पहला, पार्टी में आतंरिक लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, दूसरा - पार्टी विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी होनी चाहिए, तीसरा - संविधान की स्पिरिट को सच्चे अर्थ में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और चौथा - नेतृत्व। उन्होंने कहा कि इन चार प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर पार्टियों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण कर के ही हमारे लोकतंत्र को ज्यादा ताकतवर और मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन चारों बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करने मैं यहां आपके समक्ष आया हूं।

श्री शाह ने कहा कि सबसे पहले मैं पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि 1650 छोटी बड़ी पार्टियों में से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अन्दर आतंरिक डेमोक्रेसी बची हुई है जहां हर तीन साल में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव संविधान के अनुसार समयबद्ध तरीके से संपन्न होता है। उन्होंने कहा कि आप यह नहीं बता सकते कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये सब जानते हैं, फारुख साहब ने तो स्पष्ट ही कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में आतंरिक लोकतंत्र नहीं है, वह देश का कभी भला नहीं कर सकती, देश में परिवर्तन नहीं ला सकती।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दूसरा गुण है - ऑडियोलॉजी अर्थात् विचारधारा,यदि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, यदि देश की संसदीय व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो आइडियोलॉजी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विचारधारा का मतलब है - देश के लिए बनने वाली सभी नीतियों पर पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण उपलब्ध होना और उस दृष्टिकोण के आधार पर देश के लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से अपना पक्ष रखना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हो या वामपंथी दल या फिर क्षेत्रीय पार्टियां – उनके पास देश के लिए कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गठन तो देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए किया गया था, वह तो आजादी को प्राप्त करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हेकिल भर थी, उसकी कोई विचारधारा ही नहीं थी, उसमें सभी विचारधाराओं वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि देश जब आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को ख़त्म करने की अपील की थी लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि इसे किसी ने नहीं माना और कांग्रेस पार्टी चलती रही। बाद में इससे कई पार्टियां अलग-अलग समय पर बाहर निकलती गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं थी, साथ ही, कांग्रेस के परिवारवाद के कारण उनका आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो चुका था। उन्होंने कहा कि आज देश में केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसकी स्थापना विचारधारा के आधार पर हुई है और लगातार अपनी विचारधारा पर ही उसने आगे का सफ़र तय किया है।

श्री शाह ने कहा कि किसी पार्टी में तीसरा गुण होना चाहिए संविधान की स्पिरिट को सच्चे अर्थ में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने विकास के एक ऐसे मॉडल की कल्पना की थी जिसमें विकास समाज के अंतिम व्यक्ति को स्पर्श कर सके, उसे अन्य लोगों के सामान ही अधिकार प्राप्त हों, उनके बच्चों को भी स्वप्न देखने का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि संविधान के इसी मूलभूत उद्देश्य को पंडित दीनदयाल जी ने बाद में अंत्योदय का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की सरकार आनी चाहिए जिसके विकास का मॉडल सर्व-समावेशक और सर्व-स्पर्शीय हो। उन्होंने कहा कि देश ने चारों प्रकार की सरकार देखी है - कांग्रेस की विचारधारा, कम्युनिस्ट की विचारधारा, परिवारवाद व जातिवाद की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर चलने वाली सरकारें देखी है। उन्होंने कहा कि अब देश में

तुलनात्मक अभियान करने का समय आ गया है, चारों प्रकार के विकास के मॉडल देश की जनता के सामने है, उनके विकास के आंकड़े जनता के सामने उपलब्ध हैं - यह देखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों में क्या विकास हुआ है, कम्युनिस्ट की राज्य सरकारों में कैसा विकास हुआ है, परिवारवाद व जातिवाद के आधार पर चलने वाली क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारों के राज्य में कैसा विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कैसा विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 10 सदस्यों से जन संघ के रूप में शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी 1 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज पार्टी के 1300 से अधिक विधायक हैं, 300 से अधिक सांसद हैं, 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, 4 राज्यों में भाजपा एवं सहयोगी दलों की सरकारें हैं, देश के 60% भू-भाग और 70% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास का मॉडल कितना समृद्ध हुआ है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चौथा गुण है पार्टी का नेतृत्व। उन्होंने कहा कि 2012 के समय को याद कीजिये, जब देश में कांग्रेस-नीत यूपीए का शासन था, देश के युवाओं में गुस्सा और आक्रोश था, महिलायें अपने-आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, आये दिन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होता रहता था, सेनाओं का अपमान होता था, हमारे प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर देश का पक्ष रखने जब जाते थे तो कहीं चर्चा भी नहीं होती थी, देश की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता थी, सरकार का हर मंत्री उस वक्त अपने आप को देश का प्रधानमंत्री समझता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री मानता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लोक सभा चुनाव लड़ा और देश की जनता ने 30 साल बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास की बागडोर सौंपी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी एक गैर-कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और देश विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर हुआ।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रिफॉर्म्स के बदले ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी कार्यपद्धति का हिस्सा बनाया है। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में दो एम्स, पांच मेडिकल कॉलेज, 80 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया गया, जन-धन योजना के तहत 20 लाख से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले गए, मुद्रा योजना के तहत राज्य के हजारों युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराये गए। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार में जहां जम्मू-कश्मीर को 19 हजार करोड़ रुपये मिलते थे, अब मोदी सरकार में बढ़ कर यह लगभग 58 हजार करोड़ रुपये हो गयी है। ■

पं. दीन दयाल उपाध्याय विस्तारक योजना के अंतर्गत कश्मीर घाटी के 30 से अधिक मुस्लिम युवा जिनमें अधिकांश इंजीनियर या डबल ग्रेजुएट हैं, विस्तारक निकले हैं। इन युवाओं ने 6 माह भाजपा के विस्तारक निकलने के लिए समयदान दिया है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने इन सब युवाओं का हृदय से स्वागत किया। इन युवाओं की यह पहल भाजपा के लिए उत्साहवर्धक है।

'हमारे कार्यों से दिल्ली के गरीब लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आये'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 2 मई को नई दिल्ली के सिविक सेंटर में दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा की अभूतपूर्व जीत पर आयोजित विजय पर्व सम्मेलन में दिल्ली के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों को संबोधित किया और उनसे दिल्ली की जनता की भलाई के लिए अनवरत काम करते रहने का आह्वान किया। ज्ञात हो कि दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत को सुकमा और जम्मू-कश्मीर में देश की रक्षा करते शहीद हुए देश के वीर जांबाजों को समर्पित किया गया है। सम्मेलन की शुरुआत में सुकमा नक्सली हमले में और जम्मू-कश्मीर में सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए देश के वीर शहीदों के सम्मान में दो मिनट का मौन व्रत रख कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। इससे पहले सभा को राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री राम लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश प्रभारी श्री श्याम जाजू जी और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने भी संबोधित किया।

दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, इसके लिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी की विचारधारा के विरोधी लोग ये आस लगाए बैठे थे कि श्री नरेन्द्र मोदी जी का विजय रथ पूरे देश से घूमता-घूमता कब दिल्ली आये, उन्हें आशा थी कि शायद दिल्ली में यह विजय रथ अटक जाएगा लेकिन दिल्ली के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, रणनीति और जूनून के कारण यह विजय रथ और आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इससे पहले जो विजय मिली थी, इससे भी अनेक गुणा प्रचंड विजय दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली प्रदेश की जनता ने हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सरकार के

दिल्ली की जनता ने जो विश्वास हम पर रखा है, उस पर हम खरे उतरें और जैसे फलदार वृक्ष धरती माता की ओर झुक जाती है, उसी तरह इस विजय का धन्यवाद करते हुए हम और विनम्र व जिम्मेदार बने, तभी जाकर, हम से जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उसे हम पूर्ण कर पायेंगे।

कोई भेद होगा लेकिन मेरे लिए इन तीनों में कोई भेद नहीं है, मेरे लिए तीनों की जिम्मेदारी समान है। उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी का था और बड़े मन का परिचय देते हुए हमारे सभी निवर्तमान पार्षदों ने पूरे मनोयोग से नए पार्षदों को जिताने का महत्तम प्रयास किया, मैं मानता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी के अलावा यह कहीं और संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी पुराने पार्षदों का हृदय से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उनके मन के कार्यकर्ता को भी सलाम करना चाहता हूं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एक नई उमंग के साथ और जन-समर्थन के मिलने के विश्वास के साथ दिल्ली आगे बढ़े, यह आज के समय की बहुत बड़ी मांग है। उन्होंने कहा कि मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों को एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत हमारा गंतव्य नहीं था, हमारा लक्ष्य नहीं था, यह दिल्ली में सरकार बनाने की नींव है, यह समझकर हमारे कार्यकर्ताओं ने एमसीडी का चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां पराजय को भूल जाती है, वह पार्टी अपनी प्रगति नहीं कर सकती। उन्होंने दिल्ली एमसीडी की नई टीम का आह्वान करते हुए कहा कि वे हर पल, हर क्षण, अहर्निश इस बात को याद रखें कि आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि अगले दिल्ली विधान सभा में विजय की नींव आपके काम से दिल्ली की जनता के बीच डाली जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने जो विश्वास हम पर रखा है, उस पर हम खरे उतरें और जैसे फलदार वृक्ष धरती माता की ओर झुक जाती है, उसी तरह इस विजय का धन्यवाद करते हुए हम और विनम्र व जिम्मेदार बने, तभी जाकर, हम से जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उसे हम पूर्ण कर पायेंगे।

श्री शाह ने कहा कि 2014 के लोक सभा चुनाव में देश की जनता ने आंख मूंद कर एक बेहतर नए भारत के लिए बिना किसी विशेष अपेक्षा के भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए अपना जनादेश दिया था, लेकिन ऐतिहासिक जनादेश मिलने के बाद जब संसद के केन्द्रीय सभागार में मीटिंग हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार देश के गांव, गरीब, किसान और युवाओं को समर्पित

सरकार होगी और मेरी सरकार की जिम्मेदारी है कि देश का मान पूरी दुनिया में बढ़े। उन्होंने कहा कि मई में मोदी सरकार के तीन वर्ष पूरे होने वाले हैं, आज जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने हर बिंदु को न सिर्फ स्पर्श किया है, बल्कि उसका समाधान ढूंढने का सफल प्रयास भी किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, किसानों की भलाई के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, स्टैंड-अप, स्टार्ट-अप और स्किल इंडिया के माध्यम से देश के युवाओं को विश्व के युवाओं से प्रतिस्पर्द्धा करने का एक प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है, देश के दो करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं के घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया गया है, देश के सात करोड़ से अधिक घरों में शौचालय कर सोशल एम्पावरमेंट को एक नए तरीके से पारिभाषित किया गया है और न जाने गरीब कल्याण के कितने ही काम किये गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब-कल्याण एवं देश के विकास के लिए अहर्निश काम कर के देश के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन की जो शुरुआत की है, इससे हिन्दुस्तान आज तरक्की के पथ पर बहुत आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का छलांग लगाने का जो स्वभाव है, इस के कारण देश को भी छलांग लगाने का मौक़ा मिला है,

यह हमारा परिचय है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारी प्रेरणा का स्रोत क्या होना चाहिए, हमारा जन-प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में जनादेश मिलने के बाद हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, जनता के साथ किस तरह से संवाद स्थापित करना चाहिए, यह हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद देश का छोटा-से-छोटा व्यक्ति भी उनकी वेबसाईट पर जाकर उनसे प्रश्न पूछ सकता है, उसका जवाब भी पाता है और 'मन की बात' में शाबाशी भी। उन्होंने कहा कि एक भी महीना ऐसा नहीं गया जहां इस देश के किसी कोने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी न गए हों। उन्होंने कहा कि अभी तक 300 से अधिक जिले में प्रधानमंत्री जी का प्रवास हो चुका है, यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में शुचिता को पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी और किसी पार्टी की नहीं हैं, यह जिम्मेदारी न तो कांग्रेस की है, न ही आम आदमी पार्टी की और न ही किसी और की, यह जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा जीवन जिऐं जो उदाहरण बन जाए और उसके कारण बाकी सभी वैसा ही सार्वजनिक जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएं। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे कार्यों से जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आये। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसे दुनिया के एक मॉडल कैपिटल के रूप में कैसे विकसित किया जाए, उसका सामाजिक ताना-बाना कैसे समृद्ध किया जाए, किस तरह से राजधानी को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए, किस तरह से शासन की वैज्ञानिक पद्धति को अपना कर उसे पारदर्शी और लोकाभिमुख बनाया जाए, यह जिम्मेदारी विशेष रूप से दिल्ली के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों की है, दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की है और दिल्ली भाजपा की नई टीम की है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि आप सब से जनता की अपेक्षाएं भी हैं, इस जिम्मेदारी को हमें बखूबी निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नकारात्मकता की आँधियों के बीच भी आशा का यह दीया टिमटिमाता रहे, हम इसे और मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से यह बात आप से कहना चाहता हूं कि यह विजय आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए नहीं है, बल्कि यह विजय दिल्ली के गरीब लोगों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव लाने की विजय है, मैं मानता हूं कि हमें उसी तरह से जिम्मेदारी पूर्वक काम करना चाहिए और मुझे भरोसा है कि हम इस जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे।

श्री शाह ने कहा कि बहुत समय बाद दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक आत्मविश्वास जगाने का काम इस नगर निगम चुनाव ने किया है, इस नगर निगम के पांच साल के हमारे कार्यकाल के आधार पर हम दिल्ली में सरकार बनाएं, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देश के हर कोने के लोग रहते हैं, इसलिए दिल्ली का चुनाव ऐसे ही रेफरेंडम हो जाता है, दिल्ली के जनादेश का मतलब देश का जनादेश होता है, देश की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ है और वह मोदी जी की इस विकास-यात्रा में भागीदार बनना चाहती है, यही इसका अर्थ है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं ने जिन्होंने दिल्ली नगर निगम चुनाव की रणनीति बनाई, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया, कार्यकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित किये, सभी कार्यकर्ताओं ने एक जुट होकर मनोयोग से, संगठन के कार्यकर्ता कैसे होते हैं, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया, मैं उन सभी को हृदय से साधुवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मूल काम की शुरुआत करने वाले कार्यकर्ताओं श्री विजय मल्होत्रा, श्री मदनलाल खुराना, स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा का स्मरण करता हूं जिन्होंने दिल्ली में भाजपा की नींव रखी थी, आज नयी पीढ़ी ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। ■

जीएसएलवी ने दक्षिणी एशियाई उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया

भारत के भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी-एफ09) ने 2230 किलोग्राम भार वाले दक्षिण एशियाई उपग्रह (जीसेट-9) का 5 मई को नियोजित भू-समकालिक हस्तांतरण कक्षा (जीटीओ) में सफल प्रक्षेपण किया। यह जीएसएलवी का 11वां प्रक्षेपण था। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र एसएचएआर (एसडीएससी एसएचएआर) के दूसरे लॉच पैड से किया गया। यह स्वदेशी रूप से विकसित किए गए क्रायोजेनिक अपर स्टेज को वहन करने की दिशा में जीएसएलवी द्वारा प्राप्त की गयी लगातार चौथी सफलता है। इस अंडाकार जीटीओ, दक्षिण एशियाई उपग्रह ने अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है।

सफल प्रक्षेपण के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन दक्षिण एशिया के लिए ऐतिहासिक और बेमिसाल दिन है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि दो साल पहले भारत ने दक्षिण एशिया की जनता की प्रगति और समृद्धि के लिए उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की पहुंच उन्हें सुलभ कराने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि आशा है कि आज का प्रक्षेपण इस वादे को पूरा करने की दिशा में अहम कदम है। ■

डाकघरों को ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए त्रिपक्षीय समझौता

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों को भारत-नेट की ब्रॉडबैंड संपर्कता प्रदान करने के लिए 28 अप्रैल को बीबीएनएल, डाक विभाग और बीएसएनएल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता-दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में किया जाने वाला यह समझौता-दस्तावेज अपनी तरह का पहला त्रिपक्षीय समझौता है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.3 लाख डाकघरों और 25 हजार छोटे डाक घरों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी, ताकि ग्रामीण आबादी को लाभ हो। इस अवसर पर श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि लगभग एक लाख ग्रामीण पंचायतों को संपर्कता प्रदान करने का पहला चरण पूरा होने वाला है। शेष डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस ब्राडबैंड संपर्कता का काम दिसंबर, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। एक प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि भारत–नेट प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए 9 स्तंभों में से एक है। श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत-नेट और आज होने वाले समझौते में नागरिक सुविधाओं के प्रावधान पर बल दिया गया है। बीएसएनएल सेवा प्रदाता है जो ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा। बुनियादी ढांचा तैयार करने और संचालन खर्च डाक विभाग वहन करेगा। चूंकि भारत-नेट राष्ट्रीय नेट वर्क है, इसलिए बीबीएनएल इस पूरे संचालन का समन्वय करेगा। ■

आठ राज्यों की विधानसभाओं ने राज्य जीएसटी अधिनियम पारित किया

आठ राज्यों की विधानसभाओं ने अपने यहां एक माह से भी कम अवधि में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम को पारित कर दिया है। तेलंगाना की विधानसभा ने 09 अप्रैल 2017 को, बिहार विधानसभा ने 24 अप्रैल 2017 को, राजस्थान विधानसभा ने 26 अप्रैल 2017 को और झारखंड विधानसभा ने 27 अप्रैल, 2017 को राज्य जीएसटी विधेयक पारित कर दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 28 अप्रैल 2017 को, उत्तराखंड विधानसभा ने 02 मई 2017 को और मध्य प्रदेश विधानसभा ने 03 मई 2017 को राज्य जीएसटी विधेयक पारित कर दिया। वहीं, हरियाणा विधानसभा ने 04 मई 2017 को राज्य जीएसटी विधेयक पारित किया। इससे पहले जीएसटी परिषद ने 16 मार्च 2017 को हुई अपनी 12वीं बैठक में मॉडल राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) विधेयक को मंजूरी दी थी। शेष राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों (विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश) की विधानसभाओं द्वारा इस माह की समाप्ति से पहले अपने यहां राज्य जीएसटी विधेयक को पारित कर दिये जाने की संभावना है। केवल एक या दो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अपने यहां राज्य जीएसटी विधेयक को अगले माह के आरंभ में पारित किये जाने की संभावना है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पहले ही यह जानकारी दे दी है कि जीएसटी को 01 जुलाई, 2017 से लागू किया जाएगा। ■

पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (दिल्ली) का लगभग 60 फीसदी निर्माण कार्य पूरा

एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य से 40 लाख मानव कार्य दिवसों के रोजगार का सृजन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के अनुसार पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (दिल्ली) का लगभग 60 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस वर्ष अगस्त तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में श्री गडकरी ने 135 किलोमीटर लम्बे पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के मौजूदा निर्माण कार्य का हवाई सर्वेक्षण किया। यह एक्सप्रेसवे कोंडली से शुरू होकर गाजियाबाद होते हुए पलवल तक बनाया जा रहा है।

पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना में दो एक्सप्रेसवे हैं- पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (डब्ल्यूपीई) और पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई), जो दिल्ली के पश्चिमी एवं पूर्वी छोर से राष्ट्रीय राजमार्ग-1 और राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को जोड़ते हैं। पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (डब्ल्यूपीई) और पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) की संयुक्त परियोजना दिल्ली के चारों ओर एक रिंग रोड का स्वरूप धारण कर रही है, जिसकी कुल लम्बाई 270 किलोमीटर है। लगभग 183 किलोमीटर लम्बा एक्सप्रेसवे हरियाणा राज्य से होकर गुजर रहा है, जबकि शेष 87 किलोमीटर लम्बा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहा है।

श्री गडकरी ने कहा कि जब यह पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा, तो दोनों एक्सप्रेसवे आपस में मिलकर उन वाहनों को एक बाईपास सुलभ कराएंगे, जो दिल्ली जाने की बजाय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे पड़ोसी राज्यों की ओर अग्रसर होंगे। इससे न केवल दिल्ली में भीड़भाड़ कम हो जाएगी, बल्कि प्रदूषण भी लगभग 50 प्रतिशत घट जाएगा।

श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे नवीनतम एवं विश्वस्तरीय स्मार्ट प्रौद्योगिकी तथा सड़क सुरक्षा उपायों जैसे कि इंटेलीजेंट राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली, वीडियो घटना पहचान प्रणाली एवं एक क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम से युक्त होंगे, जिसके तहत उतना ही टोल वसूला जाएगा, जितनी दूरी तय की जाएगी।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देश का पहला हरित एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें भूदृश्य निर्माण की बेहतरीन सुविधा होगी, लगभग 2.5 लाख पेड़ लगाए जांएगे और यह सौर ऊर्जा से पूरी तरह रोशन होगा। इस एक्सप्रेसवे पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर वर्षा जल के संचयन की सुविधाएं भी होंगी। इस एक्सप्रेसवे के किनारों पर पेट्रोल पम्प, मोटल, रेस्तरां इत्यादि की भी सुविधाएं होंगी।

इन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के रोजगारों का सृजन होगा। ईपीई के निर्माण कार्य से 40 लाख मानव कार्य दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ। 2100 इंजीनियरों और 5200 श्रमिकों को दैनिक रोजगार प्राप्त होगा। इसके अलावा हरित पट्टी बरकरार रखने के लिए स्थानीय आबादी को शामिल किया जाएगा। सड़क के किनारे की सुविधाएं स्थानीय उपज के लिए बाजार मुहैया कराएंगी।

श्री गडकरी ने सूचित किया कि पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु किसानों को कुल 7700 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। श्री गडकरी ने कहा कि साजो-सामान की लागत में कमी लाने तथा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए दक्ष और एकीकृत परिवहन प्रणाली आवश्यक है। उन्होंने बताया कि देश के अन्य भागों में भी 12 एक्सप्रेसवे बनाये जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा, मुंबई-वडोदरा, बेंगलूरू-चेन्नई, हैदराबाद-विजयवाड़ा-अमरावती, हैदराबाद-बेंगलूरू, नागपुर-हैदराबाद और अमरावती रिंग रोड एक्सप्रेसवे शामिल हैं।

श्री गडकरी ने कहा कि सरकार 2,00,000 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। हम लगभग 57000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर 103933 किलोमीटर के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति बहुत तेजी से बढ़ी है। इस साल 16000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष के लिए कार्य का लक्ष्य 25000 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि निर्माण की दैनिक उपलब्धि में भी वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि तीन वर्ष पहले लगभग दो किलोमीटर प्रतिदिन थी, जो वर्तमान में लगभग 22 किलोमीटर प्रतिदिन हो चुकी है। ■

भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर

स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। यह सर्वेक्षण 434 शहरों और कस्बों में किया गया था, जिसके परिणामों की घोषणा 4 मई को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेकैंया नायडू मंत्री द्वारा की गयी। इस क्रम में भोपाल, विशाखापत्तनम, सूरत, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, नवी मुंबई, वडोदरा और चंडीगढ़ शीर्ष 10 स्वच्छ शहरों में शामिल हैं।

सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा करते हुए श्री नायडू ने कहा अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत से पहले 2014 में किए गए सर्वेक्षण से अभी तक आंध्र प्रदेश और तेलांगना के बाद मध्यप्रदेश, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने अपनी रैंकिग में काफी सुधार किया है। 2016 में किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण में 73 शहरों को शामिल किया गया था और यह राजधानी शहरों के अलावा लगभग 1 मिलियन से ज्यादा की जनसंख्या वाले शहरों में आयोजित किया गया।

मंत्री महोदय ने आगे बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 में मध्य प्रदेश और झारखंड के सभी शहरों को शामिल किया गया था और 2014 की तुलना में इन्होंने 2016 की अपनी रैंकिग में सुधार किया। राजकोट को छोड़कर गुजरात के सभी शहरों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। इसी तरह बिलासपुर को छोड़कर छत्तीसगढ़ के शहरों का अच्छा प्रदर्शन रहा। तेलंगाना के केवल दो शहरों की रैंकिंग में गिरावट आई है।

श्री नायडू ने कहा कि 50 शीर्ष स्वच्छ शहरों ने कुल 14 राज्यों का प्रधिनिधित्व किया, इन शहरों में गुजरात के 12, मध्य प्रदेश के 11, आंध्र प्रदेश के 8 और चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के एक-एक शहर शामिल हैं। वाराणसी का 2014 में 418वां रैंक था, इस वर्ष इसके रैंक में सुधार होकर 32वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह उत्तरी क्षेत्र में सबसे तेजी से स्वच्छता अपनाने वाला बड़ा शहर बन गया है।

उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब और केरल को शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों में सुधार लाने के लिए व्यापक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। हरियाणा में फरीदाबाद ने अपनी रैंक में काफी सुधार किया है। 2014 में यह 379 रैंक पर था, जबकि इस वर्ष इसने 88वीं रैंक हासिल की है। यह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सबसे तेजी से स्वच्छता अपनाने वाला शहर बन गया है।

श्री वेकैंया नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि इस वर्ष का सर्वेक्षण देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता पर नागरिकों के फैसले का परिणाम है। इसमें 37 लाख नागरिकों ने 434 नगरों और शहरों में स्वच्छता के बारे में अपनी राय उत्साहपूर्वक उपलब्ध कराई है। यह संख्या देश की कुल शहरी जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि ऐसे सर्वेक्षण सभी 4041 सांविधिक नगरों और शहरों में आयोजित किए जाएंगे।

श्री नायडू ने कहा कि भारत ने वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में अपनी स्थिति में 12 स्थानों का सुधार किया है। मीडिया के लोगों से प्राप्त फीडबैक ने भी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार होने की पुष्टि की है। श्री नायडू ने कर्नाटक के मैसूर शहर का उल्लेख करते हुए ने कहा कि इसका 2016 और 2014 में प्रथम स्थान था और इस वर्ष के सर्वेक्षण में इसे पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इस शहर में स्वच्छता में गिरावट आई है या शहर प्रशासन ने अपने प्रयासों में कमी की है।

मैसूर ने 2016-17 में कुल 2000 अंकों में 87 फीसदी अंक हासिल किए हैं, जो यह दर्शाता है कि इस वर्ष स्वच्छता के स्तर में कोई कमी आई है, हालाकि कुछ अन्य शहरों ने मैसूर से भी अधिक अंक हासिल किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रतियोगिता की भावना

को बढ़ावा मिलता है, जिससे शहरों को यह जानने में मदद मिलती है कि वे अन्य शहरों की तुलना में कहां खड़े हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पांच स्वच्छ शहरों और विभिन्न क्षेत्रों में 5 से 10 और 2-5 लाख जनसंख्या वाली श्रेणियों में सबसे साफ और तेजी से आगे बढ़ने वाले शहरों सहित 38 शहरों को पुरस्कार दिए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाने और हर घर से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट एकत्र करने, प्रोसेसिंग करने और निपटान करने के वर्तमान में चल रहे प्रयासों के आधार पर परिणामों को प्राप्त करना है। कुल 2000 अंकों में से 900 अंक ओडीएफ और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में किए गए कार्य के लिए, 600 अंक नागरिक फीडबैक के लिए और 500 अंक निष्पक्ष आंकलन के लिए निर्धारित किए गए हैं।

भारतीय गुणवत्ता परिषद ने इस वर्ष जनवरी-फरवरी के दौरान यह सर्वेक्षण आयोजित किया और 434 शहरों और नगरों में स्वच्छता स्थल निरीक्षणों के लिए 431 समीक्षक तैनात किए। इसके अलावा, सर्वेक्षण और क्षेत्र निरीक्षणों की प्रगति की वास्तविक निगरानी के लिए 55 अन्य समीक्षकों को भी शामिल किया गया। ■

बुराइयों के खिलाफ लड़ने का माद्दा हमारे भीतर ही पैदा हुआः नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को बसावा जयंती 2017 के उद्घाटन तथा बसावा समिति के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश की विशेषता रही है कि बुराइयां आई हैं, लेकिन उनके खिलाफ लड़ने का माद्दा भी हमारे भीतर ही पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 11वीं शताब्दि में भगवान बसेश्वसर ने भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सृजन किया। उन्होंने अनुभव मंडप नाम की एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जिनमें हर तरह के लोग गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो वहां आकर के सबके सामने अपने विचार रख सकते हैं। ये तो लोकतंत्र कि कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति थी। एक तरह से यह देश की पहली संसद थी। यहां हर कोई बराबर के थे। कोई ऊंच नहीं भेदभाव नहीं मेरा तेरा कुछ नहीं। श्री मोदी ने कहा कि वो कहते थे, जब विचारों का आदान प्रदान न हो, जब तर्क के साथ बहस न हो, तब अनुभव गोष्टी भी प्रासंगिक नहीं रह जाती और जहां ऐसा होता है, वहां ईश्वर का वास भी नहीं होता है। यानी उन्होंने विचारों के इस मंथन को ईश्वर की तरह शक्तिशाली और ईश्वर की तरह ही आवश्यक बताया था।

उन्होंने कहा कि इससे बड़े ज्ञान की कल्पना कोई कर सकता है। यानी सैकड़ों साल पहले विचार का सामर्थ ज्ञान का सामर्थ ईश्वर की बराबरी का है। ये कल्पना आज शायद दुनिया के लिये अजूबा है। अनुभव मंडप में अपने विचारों के साथ महिलाओं को खुल कर के बोलने की स्वतंत्रता थी। आज जब ये दुनिया हमें वीमेन एम्पावरमेंट के लिये पाठ पढ़ाती है। भारत को नीचा दिखाने के लिये ऐसी-ऐसी कल्पना विश्व में प्रचारित की जाती है।

श्री मोदी ने कहा कि ये सैंकड़ों साल पुराना इतिहास हमारे सामने मौजूद है कि भगवान बसवेश्वर ने 'वीमेन एम्पावरमेंट इक्वल पार्टनरशिप' कितनी उत्तम व्यवस्था साकार की। सिर्फ कहा नहीं व्यवस्था साकार की। समाज के हर वर्ग से आई महिलाएँ अपने विचार व्यक्त करती थीं। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं ऐसी भी होती थीं जिन्हें सामान्य समाज की बुराइयों के तहत तिरस्कृत समझा जाता था। जिनसे अपेक्षा नहीं जाती थी। जो उस समय के तथाकथित सभ्य समाज बीच में आए। कुछ बुराइयां थी हमारे यहां। वैसी महिलाओं को भी आकर के अनुभव मंडप में अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार था। महिला सशक्तिकरण को लेकर उस दौर में कितना बड़ा प्रयास था, कितना बड़ा आंदोलन था हम अंदाजा लगा सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश की विशेषता रही है। हजारों साल पुराना हमारी परम्परा है, तो बुराइयां आई हैं। नहीं आनी चाहिए। आई, लेकिन उन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का

माद्दा भी हमारे भीतर ही पैदा हुआ है। जिस समय राजाराम मोहन राय ने विधवा विवाह की बात रखी होगी। उस समय के समाज ने कितना उनकी आलोचना की होगी, कितनी कठिनाइयां आई होगी। लेकिन वो अड़े रहे। माताओं बहनों के साथ ये घोर अन्याय है। अपराध है समाज का ये जाना चाहिए।

साथ ही श्री मोदी ने यह भी कहा कि तीन तलाक को लेकर के आज इतनी बड़ी बहस चल रही है। मैं भारत की महान परम्परा को देखते हुए। मेरे भीतर एक आशा का संचार हो रहा है। मेरे मन में एक आशा जगती है कि इस देश में समाज के भीतर से ही ताकतवर लोग निकलते हैं।...आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे। आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है जो बीत रही है। उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे।

उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के ही प्रबुद्ध मुसलमान निकलेंगे जो दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखाने की ताकत रखते हैं। इस धरती की ये ताकत है और तभी तो उस कालखंड में ऊंच नीच, छूत-अछूत चलता होगा। तब भी भगवान बसवेश्वर कहते थे, नहीं उस अनुभव मंडप में आकर के उस महिला को भी अपनी बात कहने का हक है। सदियों पहले ये भारत की मिट्टी की ताकत है कि तीन तलाक के संकट से गुजर रहे हमारी माता बहनों को भी बचाने के लिये उसी समाज से लोग आएंगे।

श्री मोदी ने कहा कि मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिये। आप आगे आइये इस समस्या का समाधान कीजिए और वो समाधान का आनन्द कुछ और होगा आने वाले पीढ़ियां तक उससे ताकत लेगी। ■

हर व्यक्ति का महात्म्य है: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में वीआइपी संस्कृति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'एक नया भारत बनाना है। इसकी अवधारणा यह है कि यहां वीआइपी की जगह ईपीआइ का महत्व बढ़े। जब मैं वीआइपी की जगह ईपीआई कह रहा हूं तो ईपीआइ का मतलब है एवरी परसन इज इंपोर्टेंट। हर व्यक्ति का महत्व है, महात्म्य है। अगर 125 करोड़ देशवासियों का महात्म्य हम स्वीकार करेंगे तो महान सपनों को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी शक्ति एकजुट हो जाएगी। हम सब मिल कर यह करेंगे।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर पर हमारे देश में वीआइपी संस्कृति के प्रति एक नफ़रत का माहौल है लेकिन ये इतना गहरा है - ये मुझे अभी-अभी अनुभव हुआ। जब सरकार ने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा कर के नहीं घूमेगा। वो एक प्रकार से वीआइपी संस्कृति का सिंबल बन गया था, लेकिन अनुभव ये कहता था कि लाल बत्ती तो गाड़ी पर लगती थी, लेकिन धीरे-धीरे-धीरे वो दिमाग में घुस जाती थी और दिमागी तौर पर वीआइपी संस्कृति पनप चुका है। अभी तो लाल बत्ती गई है इसके लिये कोई ये तो दावा नहीं कर पायेगा कि दिमाग़ में जो लाल बत्ती घुस गई है वो निकल गई होगी।

नई पीढ़ी तो नकद से करीब-करीब मुक्त ही हो रही है। उसको नकद की ज़रूरत नहीं है। वो डिजिटल करेंसी में विश्वास करने लग गई है। आप तो करते हैं लेकिन इसी योजना से आप कमाई भी कर सकते हैं-आपने सोचा है। भारत सरकार की एक योजना है। अगर भीम एप्प जो कि आप डाउनलोड करते होंगे। आप उपयोग भी करते होंगे, लेकिन किसी और को रेफर करें।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरू में 'मन की बात' को लेकर के भी जब सुझाव आते थे, सलाह के शब्द सुनाई देते थे, पढ़ने को मिलते थे, तो हमारी टीम को भी यही लगता था कि ये बहुत सारे लोगों को शायद ये आदत होगी, लेकिन हमने ज़रा बारीकी से देखने की कोशिश की तो मैं सचमुच में इतना भाव-विभोर हो गया। ज़्यादातर सुझाव देने वाले लोग वो हैं, मुझ तक पहुँचने का प्रयास करने वाले लोग वो हैं, जो सचमुच में अपने जीवन में कुछ-न-कुछ करते हैं। कुछ अच्छा हो उस पर वो अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, परिस्थिति के अनुसार प्रयत्नरत हैं।

उन्होंने कहा कि ये चीजें जब ध्यान में आयी तो मुझे लगा कि ये सुझाव सामान्य नहीं हैं। ये अनुभव के निचोड़ से निकले हुए हैं। कुछ लोग सुझाव इसलिये भी देते हैं कि उनको लगता है कि अगर यही विचार वहाँ, जहाँ काम कर रहे हैं, वो विचार अगर और लोग सुनें और उसका एक व्यापक रूप मिल जाए तो बहुत लोगों को फायदा हो सकता है और इसलिये उनकी स्वाभाविक इच्छा रहती है कि 'मन की बात' में अगर इसका ज़िक्र हो जाए। श्री मोदी ने कहा कि ये सभी बातें मेरी दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक हैं। मैं सबसे पहले तो अधिकतम सुझाव जो कि कर्मयोगियों के हैं, समाज के लिये कुछ-न-कुछ कर गुज़रने वाले लोगों के हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी तो नकद से करीब-करीब मुक्त ही हो रही है। उसको नकद की ज़रूरत नहीं है। वो डिजिटल करेंसी में विश्वास करने लग गई है। आप तो करते हैं लेकिन इसी योजना से आप कमाई भी कर सकते हैं-आपने सोचा है। भारत सरकार की एक योजना है। अगर भीम एप्प जो कि आप डाउनलोड करते होंगे। आप उपयोग भी करते होंगे, लेकिन किसी और को रेफर करें। किसी और को जोड़ें और वो नया व्यक्ति अगर तीन ट्रांजेक्शन करे, आर्थिक कारोबार तीन बार करे, तो इस काम को करने के लिये आपको 10 रुपये की कमाई होती है। आपके खाते में सरकार की तरफ से 10 रुपये जमा हो जायेगा। अगर दिन में आपने 20 लोगों से करवा लिया तो आप शाम होते-होते 200 रुपये कमा लेंगे। व्यापारियों को भी कमाई हो सकती है, विद्यार्थियों को भी कमाई हो सकती है और ये योजना 14 अक्टूबर तक है। डिजिटल इंडिया बनाने में आपका योगदान होगा। ■

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)................................ (2)....................................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :.................................. दिनांक :............................ बैंक : ....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

केदारनाथ (उत्तराखंड) में जन–अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली में नीति आयोग संचालन परिषद् की तीसरी बैठक को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

शिमला स्थित ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते श्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथिः (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघरः लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली
36 पृष्ठ कवर सहित
"रजिस्टर्ड"
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने कमल संदेश के आजीवन सदस्य

कमल संदेश की कैशलेस सदस्यता लें!

आह्वान

आपको जानकर हर्ष होगा कि 6 दिसम्बर 2016 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा 'कमल संदेश' का आजीवन सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. **श्री अमित शाह** ने पत्रिका की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 'कमल संदेश' भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय पत्रिका है और यह पाक्षिक रूप में हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है।

हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 5000/– रुपए का चैक देकर 'कमल संदेश' की आजीवन सदस्यता ली। साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर सहित अनेक केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आजीवन सदस्यता ग्रहण की गई है।

'कमल संदेश' हिन्दी एवं अंग्रेजी के दोनों अंकों को 5000/– (पांच हजार रुपये) की सदस्यता शुल्क देकर नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब 'कमल संदेश' के लिए कैशलेस भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है। कृपया 5000/– (पांच हजार) रुपये का योगदान कर आप भी 'कमल संदेश' (हिन्दी+अंग्रेजी) का आजीवन सदस्य बनें।

एक साल (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹350/-	**तीन साल** (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹1000/-
आजीवन (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹3000/-	**आजीवन** (हिन्दी+अंग्रेजी)	—	₹5000/-

'कमल संदेश' के हमारे पाठकों से अनुरोध है कि इसकी सदस्यता लेकर जीवंत वैचारिक आंदोलन के भागीदार बनें।

कैशलेस बना 'कमल संदेश'

सदस्य बनें और बनाएं

☞ **www.kamalsandesh.org, www.bjp.org** पर जाकर कैशलेस भुगतान क्रेडिट/डेबिट/नेटबैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।

☞ साथ ही दिए बार कोड से मोबाइल द्वारा सीधा भुगतान भी कर सकते हैं।

chillr
ACCEPTED HERE
Scan the QR code to make a payment
Click on SCAN & PAY and enter amount
Add this contact to pay
+91 9911026172

"**कमल संदेश**" के नाम से कृपया चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
कमल संदेश, पीपी–66, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003